[2020] 14 एससीआर 45 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

झारखंड राज्य और अन्य।

बनामो

ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड, रांची और अन्य।

(2020 की सिविल अपील संख्या 3860-3862) 01 दिसंबर, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा, जे.जे.]

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 - धारा.9 - झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 - औद्योगिक नीति 2012 को राज्य सरकार द्वारा 16.06.2012 को अधिसूचित किया गया था जिसमें पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क के 50 प्रतिशत के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी - नीति में परिकल्पना की गई थी कि औद्योगिक इकाइयां उत्पादन की तारीख के अगले वित्तीय वर्ष से केवल विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रतिपूर्ति/सब्सिडी आदि के भुगतान के लिए हकदार होंगी - यह भी नीति में निर्धारित किया गया है कि औद्योगिक नीति की शर्तों को लागू करने वाली अधिसूचनाएं राज्य सरकार के विभागों द्वारा एक महीने की अवधि के भीतर जारी की जाएंगी - राज्य सरकार के विभाग एक महीने की समय अनुसूची का पालन करने में विफल रहे - आखिरकार, राज्य सरकार ने 08.01.2015 को एक छूट अधिसूचना जारी की, लेकिन इसे उस तारीख से प्रभावी बना दिया जिस पर इसे जारी किया गया था - प्रतिवादी द्वारा रिट याचिका - उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादी ने दावा किया कि अधिसूचना में इसे भावी बनाने वाले खंड को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह औद्योगिक नीति 2012 द्वारा आयोजित प्रतिनिधित्व के विपरीत था - वैकल्पिक रूप से, प्रतिवादी ने एक निर्देश मांगा कि वह अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क से छूट का हकदार होगा - उच्च न्यायालय ने कहा कि देरी का कोई विशेष कारण नहीं था और कि 'लेकिन राज्य के अधिकारियों के सुस्त दृष्टिकोण के लिए' छूट औद्योगिक नीति 2012 के जारी होने के एक महीने के भीतर जारी की जानी चाहिए थी - उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.01.2015 को भावी प्रभाव से नहीं माना जाना

चाहिए और इसे भावी बनाने वाले खंड को रद्द करना होगा - अधिसूचना को प्रभावी माना गया था औद्योगिक नीति 2012 की तारीख (1 अप्रैल 2011) - वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए जमा बिजली शुल्क को समायोजित करने का निर्देश दिया गया था- बिजली शुल्क के प्रति प्रतिवादी की भविष्य की देयता - अपील पर, आयोजित किया गया: राज्य सरकार ने धारा 9 के तहत एक वैधानिक अधिसूचना जारी की, लेकिन 08.01.2015 से प्रभावी रूप से ऐसा करके इसने औद्योगिक नीति 2012 में आयोजित प्रतिनिधित्व की प्रकृति को नकार दिया - नीति के कारणों पर असर डालने वाला बिल्कुल कोई औचित्य नहीं या अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सार्वजनिक हित की पेशकश की गई है - चूंकि राज्य ने अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए कोई औचित्य नहीं दिया है, या इसके सार्वजनिक हित में होने के कारण प्रदान किए हैं, इसलिए राज्य द्वारा कार्रवाई का ऐसा तरीका मनमाना है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। प्रतिवादी बिजली शुल्क से छूट/कटौती का हकदार है - हालांकि, प्रतिवादी वित्त वर्ष 2011-12 के लिए छूट/कटौती का हकदार नहीं होगा - औद्योगिक नीति 2012 के संदर्भ में, उत्पादन शुरू होने के बाद वित्तीय वर्ष से पात्रता प्राप्त होती है - प्रतिवादी ने 17.08.2011 को उत्पादन शुरू किया - इसलिए, वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है।

सिद्धांत/सिद्धांत -

वचन पत्र - उत्पत्ति और विकास - चर्चा की।

सिद्धांत/सिद्धांत - वचन और वैध अपेक्षा - के बीच अंतर - चर्चा की। अपीलों का निपटान करते हुए, न्यायालय ने आयोजित किया: झारखंड राज्य द्वारा अपेक्षाओं का उल्लंघन

1.वर्तमान मामले में, यह न्यायालय राज्य के सबमिशन में किसी भी पदार्थ को देखने में असमर्थ है जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष बचाव में आग्रह किया गया था। वर्तमान मामले में न केवल राज्य ने एक गंभीर प्रतिनिधित्व किया, बल्कि यह प्रतिनिधित्व राज्य में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने की अपनी घोषित इच्छा पर स्थापित किया गया था। नीति दस्तावेज में कहा गया है:

(i) प्रोत्साहनों की प्रकृति;

---

[1] "औद्योगिक नीति 2012"

[2] "बिहार अधिनियम 1948"

(ii) वह अवधि जिसके दौरान प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे;

(iii) औद्योगिक नीति 2012 के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने विभागों के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जाने की समय-सीमा। [पैरा 43] [78-एफ-एच]

2. राज्य ने उपरोक्त शर्तों में एक गंभीर प्रतिनिधित्व किया है, यह स्पष्ट रूप से जी अनुचित और मनमाना होगा कि राज्य के भीतर औद्योगिक इकाइयों को उनके वैध अधिकार से वंचित किया जाए। राज्य सरकार ने वास्तव में, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 9 के तहत एक वैधानिक अधिसूचना जारी की, लेकिन 8 जनवरी 2015 से प्रभावी, भविष्य में ऐसा करके इसने औद्योगिक नीति 2012 में प्रतिनिधित्व की प्रकृति को नकार दिया। अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के एच समक्ष नीति या जनहित के कारणों पर असर डालने वाला कोई औचित्य पेश नहीं किया गया है। दलीलें सरकार की ओर से देरी के कारणों पर पूरी तरह से चुप हैं औद्योगिक नीति 2012 में प्रतिनिधित्व की शर्तों के विपरीत, छूट को संभावी बनाने के लिए कोई औचित्य प्रदान नहीं करती हैं। [पैरा 44] [79-ए-सी]

3. राज्य के लिए यह दावा करना एक बात है कि रिट याचिकाकर्ता के पास कोई निहित अधिकार नहीं था, लेकिन राज्य के लिए यह दावा करना बिल्कुल दूसरी बात है कि औद्योगिक नीति 2012 में परिकल्पित अवधि के भीतर छूट अधिसूचना को प्रभावी नहीं करने के अपने कारणों का खुलासा करना कर्तव्य नहीं है। राज्य की जवाबदेही और नीतिगत दस्तावेज के संदर्भ में उसने जो गंभीर दायित्व निभाया है, दोनों ही राज्य शक्ति की ऐसी धारणा को स्वीकार करने के खिलाफ हैं। राज्य को औपनिवेशिक धारणा को त्याग देना चाहिए कि यह एक संप्रभु है जो अपनी इच्छा से खैरात सौंपता है। इसकी नीतियां वैध अपेक्षाओं को जन्म देती हैं कि राज्य सार्वजनिक दायरे में जो कुछ भी सामने रखता है उसके अनुसार कार्य करेगा।अपने सभी कार्यों में, राज्य निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य है। यह मनमानी राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी की एक प्राथमिक आवश्यकता है जिसे संविधान का अनुच्छेद 14 अपनाता है। निजी नागरिकों और निजी व्यवसाय के अधिकार से वंचित होना सार्वजनिक हित में आधारित आवश्यकता के अनुपात में होना चाहिए। राज्य शक्ति की इस अवधारणा को इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक सुसंगत पंक्ति में मान्यता दी गई है। [पैरा 45] [79-सीएफ]

4. इसलिए, यह स्पष्ट है कि राज्य ने औद्योगिक नीति 2012 के तहत प्रतिवादी और इसी तरह स्थित औद्योगिक इकाइयों को एक प्रतिनिधित्व दिया था। इस अभ्यावेदन ने उनकी ओर से एक जायज अपेक्षा को जन्म दिया कि उन्हें अगले पांच वर्षों के एफ लिए बिजली शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट/कटौती की पेशकश की जाएगी। हालांकि,निर्धारित समय के भीतर अधिसूचना जारी करने में विफलता के कारण और केवलभावी रूप से छूट प्रदान करने के कारण, राज्य में अपेक्षा और विश्वास का उल्लंघन हुआ। चूंकि राज्य ने अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए कोई औचित्य नहीं दिया है, या इसके सार्वजनिक हित में होने के कारण बताए हैं, इसलिए राज्य द्वारा इस तरह की कार्रवाई मनमानी है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। [पैरा 46] [80-ए-सी]

5. संकीर्ण मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी बिजली शुल्क से छूट/कटौती का हकदार है जिसका उत्तर सकारात्मक में दिया गया है। तथापि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रतिवादी वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए छूट/कटौती का हकदार नहीं होगा। औद्योगिक नीति 2012 के खंड 35.7 (बी) के अनुसार, पात्रता उत्पादन शुरू होने के बाद वित्तीय वर्ष से शुरू होती है। प्रतिवादी ने 17 अगस्त 2011 को उत्पादन सी शुरू किया। इसलिए, वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करनी होगी। अंत में, यह न्यायालय उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के सी साथ सहमत है कि प्रतिवादी बिजली शुल्क से छूट का हकदार था, हालांकि इस निर्णय में बताए गए कारणों के लिए. इसके अलावा, दी गई राहत वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 तक ही सीमित रहेगी। [पैरा 51] [85-बी-डी]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम बनाम एस. रघुनाथन **(1998) 7 एससीसी 66: [1998] 1 सप्ल. एससीआर 156;** *मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड बनाम भारत संघ* **(2012) 11 एससीसी 1: [2012] 7 एससीआर 644;** *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी* **(2016) 4 एससीसी 236: [2016] 2 एससीआर 426;** *भारतीय खाद्य निगम बनाम कामधेनु मवेशी चारा उद्योग* **(1993) 1 एससीसी 71: [1992] 2 सप्ल. एससीआर 322;** *नोएडा उधमिता संगठन बनाम नोएडा* **(2011) 6 एससीसी 508: [2011] 8 एससीआर एफ 25;** *इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया* **(2011) 8 एससीसी 161: [2011] 9 एससीआर 146 - पर भरोसा।**

[1] "औद्योगिक नीति 2012"

[2] "बिहार अधिनियम 1948"

बिहार राज्य बनाम कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड **(2010) 3 एससीसी 274: [2010] 1 एससीआर 928** *मैनुएलसंस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य* **(2016) 6 एससीसी 766: [2016] 3 एससीआर 718;** *मोतीलाल पदमपत सागर मिल्स कंपनी लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य* **(1979) 2 एससीसी 409: [1979] 2 एससीआर 641;** *मध्य प्रदेश राज्य बनाम भाईलाल भाई* **एआईआर 1964 एससी 1006: [1964] एससीआर 261***; सुगनमल बनाम मध्य प्रदेश राज्य* **एआईआर 1965 एससी 1740;** *मफतलाल उधयोग लिमिटेड बनाम भारत संघ* **(1997) 5 एससीसी 536:[1996] 10 सप्ल. एससीआर 585;** *अमरजीत सिंह अहलूवालिया (डॉ) बनाम पंजाब राज्य,* **(1975) 3 एससीसी 503: [1975] 3 एससीआर 82;** *सुखदेव सिंह बनाम भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी,* **(1975) 1 एससीसी 421: [1975] 3 एससीआर 619 (न्यायमूर्ति केके मैथ्यू की सहमति के अनुसार) और** *रमण दयाराम शेट्टी बनाम अंटेराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारत* **(1979) 3 एससीसी 489: [1979] 3 एससीआर 1014**; पटना बनाम मदन मोहन प्रसाद **के न्यायिक उच्च न्यायालय (2011) 9 एससीसी 65: [2011] 13 एससीआर 972***; दयाल सिंह बनाम भारत संघ* **(2003) 2 SCC 593: [2003] 1 SCR 714;** *हिंदुस्तान भूतेल समिति लिमिटेड बनाम डॉली दास* **(1999) 4 एससीसी 450 - संदभत।**

क्रैब बनाम अरुण **डीसी [1976] 1 चौधरी 179 27;** *कॉम्बे बनाम कॉम्बे* **[1951] 2 केबी 21529; वायवर्न डेवलपमेंट, रे, [1974] 1 डब्ल्यूएलआर 1097** *टंगस्टन वैद्युतकशास्त्र कंपनी लिमिटेड बनाम उपकरण, धातु उत्पादन कंपनी लिमिटेड,* **[1955] 1 डब्ल्यूएलआर 761,** *बेयर्ड कपड़ा स्वामित्व लिमिटेड बनाम मार्क्स एवं स्पेंसर पीएलसी,* **[2002] 1 ऑल ईआर (कॉम) 737,** *वाल्टन स्टोर्स (इंटरस्टेट) लिमिटेड बनाम माहर*, **(1988) 164 सीएलआर 387। 30;** *आर बनाम उत्तर और पूर्व डेवोन स्वास्थ्य प्राधिकरण, पूर्व पी कफ़लान* **[2001] क्यूबी 213***; रेजिना (बीबी) बनाम न्यूहैम लंदन बरो काउंसिल* **[2002] 1 डब्ल्यूएलआर 23734***; विटारेली बनाम सेटन* **359 यूएस 535 ए (1959); ईस्ट ससेक्स काउंटी काउंसिल [2003] 1 डब्ल्यूएलआर 348***; न्यू साउथ वेल्स बनाम क्विन के लिए*

अटॉर्नी जनरल **(1990) 64 ऑस्ट एलजेआर 327: (1990) 170 सीएलआर 1;** *रेजिना (रेप्रोटेक (पेबशम) लिमिटेड) बनाम ईस्ट ससेक्स* **बी** *काउंटी काउंसिल* **[2003] 1 डब्ल्यूएलआर 348 - रेफरह्यूग बीले, चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स (32 वां संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल 2017)। हैरी वूल्फ और अन्य, डी स्मिथ की न्यायिक समीक्षा (8 वां संस्करण, थॉमसन रॉयटर्स 2018)। एम.पी. जैन और एस. एन. जैन, प्रशासनिक कानून के सिद्धांत (7वां संस्करण, ईबीसी 2013) - संदर्भित**

<u>केस लॉ रेफरेंस</u>

[2010] 1 SCR 928	**को संदर्भित**	**पैरा 11**
[2016] 3 SCR 718	**को संदर्भित**	**पैरा 11**
[1979] 2 SCR 641	**को संदर्भित**	**पैरा 11**
[1964] SCR 261	**को संदर्भित**	**पैरा 14(x)**
AIR 1965 SC 1740	**को संदर्भित**	**पैरा 14(x)**
[1996] 10 Suppl. SCR 585	**को संदर्भित**	**पैरा 14(xii)**
[1975] 3 SCR 82	**को संदर्भित**	**पैरा 38**
[1975] 3 SCR 619	**को संदर्भित**	**पैरा 38**
[1979] 3 SCR 1014	**को संदर्भित**	**पैरा 38**
[1998] 1 सप्ल। SCR 156	**को संदर्भित**	**पैरा 39**
[2012] 7 SCR 644	**पर निर्भर**	**पैरा 40**
[2016] 2 SCR 426	**पर निर्भर**	**पैरा 41**
[1992] 2 सप्ल। SCR 322	**पर निर्भर**	**पैरा 42**
[2011] 8 SCR 2	**पर निर्भर**	**पैरा 42**
[2011] 13 SCR 972	**पर निर्भर**	**पैरा 42**
[2003] 1 SCR 714	**को संदर्भित**	**पैरा 42**
(1999) 4 एससीसी 450	**को संदर्भित**	**पैरा 48**
[2011] 9 एससीआर 146	**पर निर्भर**	**पैरा 50**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2020 की सिविल अपील संख्या 3860- 3862

---

[1] "औद्योगिक नीति 2012"

[2] "बिहार अधिनियम 1948"

झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.12.2019 से 2019 की रिट याचिका (टी) संख्या 4274, 2019 की रिट याचिका (टी) संख्या 4275 और 2019 की रिट याचिका (टी) संख्या 4320 में उपस्थित पक्षों के लिए एएजी, आदित्य प्रताप सिंह, सुश्री भाश्वती सिंह, देवाशीष भरुका श्रीमती जया भरुका, रवि भरुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, सुश्री सृष्टि अग्रवाल, एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे

क अपील
ख मुद्दा
ग कैप्टिव विद्युत संयंत्र विद्युत शुल्क का आकलन
घ औद्योगिक नीति 2012
ङ उच्च न्यायालय के समक्ष विद्युत शुल्क से छूट
च वकील की प्रस्तुतियां
एच विश्लेषण
एच .1 नीतिगत प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन में
एच 2 **पदमपत** पर भवन
एच 3 वचनपत्र - उत्पत्ति और विकास
एच 4 एस्टोपेल से अपेक्षाओं तक
एच 5 भारतीय कानून और वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत
एच 6 झारखंड राज्य द्वारा उल्लंघन की गई अपेक्षाएं
एच 7 दावे के तकनीकी बचाव ।
छ निष्कर्ष

अनुमति दी गई।

ए. अपील

2. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय के एक फैसले से उत्पन्न हुई है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा शुरू की गई याचिका की अनुमति देते हुए, खंड पीठ :

राज्य सरकार द्वारा में जारी दिनांक 8 जनवरी 2015 की अधिसूचना के अंतिम पैराग्राफ को रद्द कर दिया।

i) वाणिज्यिक कर विभाग, झारखंड औद्योगिक नीति, 2012[1] के तहत दी जाने वाली बिजली शुल्क से छूट/कटौती को संभावित प्रभाव देते हुए;

ii) निदेश दिया कि अधिसूचना को 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी माना जाएगा, जब औद्योगिक नीति 2012 भूतलक्षी प्रभाव से लागू की गई थी; और

iii) प्रतिवादी के दावे को बरकरार रखा कि वह औद्योगिक नीति 2012 में किए गए प्रतिनिधित्व के संदर्भ में बिजली शुल्क से छूट/कटौती का हकदार था, और यह कि राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए छूट से इनकार करना *वचन पत्र के सिद्धांत* के विपरीत था।

राज्य 11 दिसंबर 2019 के फैसले को चुनौती देने के लिए अपील में है।

बी. मुद्दा

3. निर्धारण के लिए मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी वितीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए बिजली शुल्क के लिए मूल्यांकन की गई राशि के 50 प्रतिशत की छूट या कटौती का दावा करने का हकदार है। प्रतिवादी औद्योगिक नीति 2012 (अपीलकर्ता द्वारा 16 जून 2012 को अधिसूचित) और बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948[2] की धारा 9 के तहत जारी 8 जनवरी 2015 की एक वैधानिक अधिसूचना के आधार पर अपनी पात्रता का दावा करता है. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत झारखंड राज्य के लिए 15 नवंबर 2000 से बिहार अधिनियम 1948 को अपनाया गया था।

सी. आबद्ध विद्युत संयंत्र: बिजली शुल्क का आकलन

---

[1] "औद्योगिक नीति 2012"

[2] "बिहार अधिनियम 1948"

4. प्रतिवादी को 31 मई 2013 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने का प्रमाण पत्र दिया गया था। प्रमाण पत्र में दर्ज है कि स्पंज आयरन और नरम इस्पात बिलेट्स की एकीकृत विनिर्माण इकाई, प्रतिवादी द्वारा स्थापित 20 मेगावाट क्षमता के कैप्टिव थर्मल प्लांट के साथ मिलकर 17 अगस्त 2011 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। बिहार (झारखंड) विद्युत शुल्क नियम 1949[3] के नियम 4 के तहत 22 नवंबर 2011 को प्रतिवादी को पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसके अनुसार वह वितरण के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था और/या 1 "औद्योगिक नीति 2012" 2 "बिहार अधिनियम 1948" 3 "बिहार नियम 1949" 53 1 अक्टूबर 2011 से ऊर्जा की खपत। बिहार नियम 1949 के नियम 9 के साथ पठित फॉर्म-III में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के आधार पर, निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए 9 दिसंबर 2014 को, वित्त वर्ष 2012-13 के लिए 18 दिसंबर 2015 को और वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 16 दिसंबर 2016 को मूल्यांकन आदेश पारित किए गए थे।

डी. औद्योगिक नीति 2012

5. औद्योगिक नीति 2012 को राज्य सरकार द्वारा 16 जून 2012 को अधिसूचित किया गया था। औद्योगिक नीति 2012 की कुछ मुख्य विशेषताओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है

i) खंड 32.10 में स्व-उपभोग अथवा कैप्टिव उपयोग के लिए स्थापित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के 50% के भुगतान से छूट प्रदान की गई है

   “32.10 आबद्ध विद्युत संयंत्र स्थापित करने वाली

   नई या मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को इसके चालू होने की तारीख से स्व-उपभोग या कैप्टिव उपयोग के लिए पांच साल की अवधि (यानी संयंत्र द्वारा उपयोग की जा रही बिजली के संबंध में)

ii) खंड 35.7 (बी) में परिकल्पना की गई है कि उत्पादन की तारीख (डीओपी) के बाद वित्तीय वर्ष से पात्रता सुनिश्चित होगी:

[3] "बिहार नियम 1949"

"35.7 (बी) औद्योगिक इकाइयां डीओपी के अगले वित्तीय वर्ष से केवल विभिन्न श्रेणियों के तहत सब्सिडी / प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति/भुगतान के लिए हकदार होंगी।

iii) खंड 38 (ख) में यह निर्धारित किया गया है कि औद्योगिक नीति की शर्तों को लागू करने वाली अधिसूचनाएं राज्य सरकार के विभागों द्वारा एक माह की अवधि के भीतर जारी की जाएंगी।

"38 **निगरानी और समीक्षा**

(बी) सभी संबंधित विभाग और संगठन इस नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए एक महीने के भीतर आवश्यक अनुवर्ती अधिसूचनाएं जारी करेंगे। इस नीति के कार्यान्वयन की विधिवत निगरानी सरकार मुख्य सचिव के स्तर पर एक तिमाही में कम से कम एक बार, ताकि राज्य सरकार इस नीति की मध्यावधि समीक्षा कर सके।

ई. विद्युत शुल्क से छूट

6. हालांकि औद्योगिक नीति 2012 जिसे 16 जून 2012 को अधिसूचित किया गया था, ने परिकल्पना की थी कि राज्य सरकार के विभागों द्वारा अधिसूचनाएं एक महीने के भीतर जारी की जाएंगी, लेकिन समय अनुसूची का पालन करने में विफलता थी। को प्रभावी करने के लिए, बिहार अधिनियम 1948 की धारा 9 के तहत एक अधिसूचना आवश्यक थी। धारा 9 छूट देने के लिए राज्य सरकार की शक्ति को मान्यता देती है[4]।

7. बिहार नियम 1949 का नियम 6 प्रत्येक निर्धारिती पर शुल्क का भुगतान करने के लिए एक कर्तव्य डालता है जो उस महीने के दो कैलेंडर महीनों के भीतर देय होता है जिससे वह संबंधित है। नियम 9 में उस महीने की समाप्ति से दो कैलेंडर महीनों की अवधि के भीतर फॉर्म- III में रिटर्न जमा करने की आवश्यकता होती है, जिससे रिटर्न संबंधित होता है[5]।

8. चूंकि धारा 9 के तहत झारखंड राज्य द्वारा छूट अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, इसलिए उषा मार्टिन लिमिटेड[6] के नाम से एक कंपनी द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के

---

[5] **नियम 6. शुल्क का भुगतान** - प्रत्येक निर्धारिती उस महीने के दो कैलेंडर महीनों के भीतर धारा 4 के तहत देय शुल्क की पूरी राशि का भुगतान करेगा, जिससे शुल्क संबंधित है।

नियम 9. विवरणी प्रस्तुत करना - प्रत्येक निर्धारिती सर्कल या उप-सर्कल के उपयुक्त निरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जैसा भी मामला हो, फॉर्म III में एक रिटर्न, उस महीने की समाप्ति से दो कैलेंडर महीनों के भीतर, जिससे रिटर्न संबंधित है। विवरणी का उसमें दर्शाए गए तरीके से सत्यापन किया जाएगा और निर्धारिती अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। जब एक निर्धारिती के पास एक से अधिक लाइसेंस होते हैं, तो प्रत्येक लाइसेंस के संबंध में अलग-अलग विवरणियां प्रस्तुत की जाएंगी। 2014 का

[6] डब्ल्यूपी (टी) संख्या 6008, 3/4 फरवरी 2015 को निर्णय लिया गया

समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी। आखिरकार, राज्य सरकार ने 8 जनवरी 2015 को एक छूट अधिसूचना जारी की, लेकिन इसे जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी बना दिया। छूट अधिसूचना नीचे निकाली गई है:

> "एस. ओ .67 दिनांक 8 जनवरी, 2015 - झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के पैरा 32.10 के आलोक में और शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त झारखंड के राज्यपाल ने स्वयं उपभोग या कैप्टिव उपयोग (संयंत्र द्वारा उपयोग की जा रही बिजली के संबंध में) के लिए आबद्ध विद्युत संयंत्र स्थापित करने वाली नई या मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को पावर प्लांट के चालू होने की तारीख से 50% बिजली शुल्क के भुगतान से छूट दी है। यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी और झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित अवधि तक प्रभावी रहेगी।

9. औद्योगिक नीति 2012 ने उत्पादन शुरू होने से पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क पर छूट या कटौती के रूप में प्रोत्साहन की घोषणा की। यदि औद्योगिक नीति 2012 द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा एक महीने के भीतर धारा 9 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी, तो प्रतिवादी को नीति द्वारा अपेक्षित छूट की लगभग पूरी अवधि का लाभ मिला होगा। लेकिन चूंकि 8 जनवरी 2015 की छूट अधिसूचना को भावी बनाया गया था, इसलिए प्रतिवादी (और अन्य समान इकाइयों) को बहुत कम अवधि के लिए बिजली शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त होगा। इस स्थिति का सामना करते हुए, प्रतिवादी ने अगस्त 2019 में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही शुरू की।

उच्च न्यायालय के समक्ष

10. *वचन पत्र* के सिद्धांत पर निर्भरता रखते हुए, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी प्रस्तुतियों में, दो राहतों या निर्देशों में से एक की मांग की। सबसे पहले, प्रतिवादी ने दावा किया कि अधिसूचना में इसे भावी बनाने वाले खंड को हटा दिया जाना

चाहिए क्योंकि यह औद्योगिक नीति 2012 द्वारा आयोजित प्रतिनिधित्व के विपरीत था। वैकल्पिक रूप से, प्रतिवादी ने यह निर्देश मांगा कि वह अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क से छूट का हकदार होगा (औद्योगिक नीति 2012 के तहत परिकल्पित अवधि पांच साल की अवधि)।

11. उच्च न्यायालय ने **बिहार राज्य** बनाम **कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड**[7] **("कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड") और मैनुएलसंस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **केरल राज्य**[8] 7 (2010) 3 एससीसी 274 में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए ऊपर उल्लिखित दो कार्यों में से पहले को स्वीकार कर लिया। **("मैनुएलसन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड")**। ये निर्णय **मोतीलाल पदमपत सागर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम यूपी**[9] **राज्य ("मोतीलाल पदमपत")** में प्रतिपादित वचन पत्र के सिद्धांत पर आधारित हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य में कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने वाली सभी नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को स्व-उपभोग या कैप्टिव उपयोग के लिए पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ देने का वादा किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला नहीं था कि वह इन औद्योगिक इकाइयों को लाभ देने का इरादा नहीं रखती थी, क्योंकि तथ्य की बात के रूप में, उसने 8 जनवरी 2015 को एक अधिसूचना जारी की थी, हालांकि देर से।

12. छूट अधिसूचना जारी करने में सरकार की ओर से देरी के साथ गलती खोजते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि देरी का कोई विशेष कारण नहीं था और "लेकिन राज्य के अधिकारियों के सुस्त दृष्टिकोण के लिए" छूट औद्योगिक नीति 2012 के जारी होने के एक महीने के भीतर जारी की जानी चाहिए थी। देर से जारी अधिसूचना का प्रभाव औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा किए गए वादे के लाभ से वंचित करना था। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह लाभ वित्त वर्ष 2011-12 से पांच साल की अवधि के लिए दिया जाना था जो वित्त वर्ष 2015-16 में समाप्त हो गया था। चूंकि छूट अधिसूचना 8 जनवरी 2015 को जारी की गई थी, इसलिए प्रतिवादी की इकाई और इसी तरह की इकाइयों को वादा किए गए पांच साल के बजाय केवल एक या दो साल के लिए लाभ प्राप्त होगा, जैसा कि औद्योगिक नीति 2012 में परिकल्पना की गई थी। इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह था कि समय के भीतर छूट अधिसूचना जारी करने में

---

[7] (2010) 3 एससीसी 274

[8] (2016) 6 एससीसी 766

[9] (1979) 2 एससीसी 409

राज्य की विफलता औद्योगिक इकाइयों को वह लाभ प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए जिसका वादा किया गया था और वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए इस तरह के लाभ से इनकार करना वचनबद्धता के सिद्धांत के विपरीत था।

(घ) विद्युत शुल्क के प्रति प्रतिवादी की भावी देयता के विरुद्ध समायोजित करने का निदेश दिया गया था। चूंकि राशि पहले ही जमा की जा चुकी है, कोई धनवापसी नहीं है, लेकिन भविष्य के भुगतानों का समायोजन निर्देशित किया गया था।

13. राज्य अपील में है।

छ. वकील की प्रस्तुतियाँ

14. झारखंड राज्य के लिए पेश होने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री तापेश कुमार सिंह प्रस्तुत करते हैं कि:

i) औद्योगिक नीति 2012 के तहत स्वीकार्य छूट/रियायत के संदर्भ में, प्रतिवादी को बिजली शुल्क के भुगतान से छूट के लिए दावा करने के लिए फॉर्म- III के कॉलम 6 (iv) द्वारा आवश्यक था;

ii) प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी तीन रिटर्न में, केवल "सहायक खपत" के लिए छूट/कटौती की मांग की गई थी, जिसे मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था और अनुमति दी गई थी;

iii) कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष मांगी गई छूट/कटौती के दावे के अभाव में, निर्धारण अधिकारी प्रतिवादी को रियायत नहीं दे सकता था;

iv) तीन मूल्यांकन आदेश दर्शाते हैं कि प्रतिवादी ने विरोध या निंदा के बिना बिजली शुल्क का भुगतान किया, और देय राशि के निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई गणना स्वीकार की गई; (

v) तदनुरूपी निर्धारण वर्षों के लिए प्रतिवादी द्वारा दायर की गई तीन विवरणियां देर से की गई थीं और जुर्माने के रूप में 2000/- रुपए की राशि उद्ग्रहीत की गई थी;

vi) यह प्रस्तुत करना कि बिहार अधिनियम, 1948 की धारा 9 के तहत अधिसूचना 8 जनवरी 2015 को देर से जारी की गई थी, प्रतिवादी के लिए

उपलब्ध नहीं है क्योंकि तीन में से दो मूल्यांकन आदेश अधिसूचना जारी होने के ग्यारह महीने और तेईस महीने बाद जारी किए गए थे। इसलिए, वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के मूल्यांकन आदेशों में, अधिसूचना के देरी से जारी होने से प्रतिवादी को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है;

vii) वित्त वर्ष 2011-12 के लिए, प्रतिवादी द्वारा सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि औद्योगिक नीति 2012 की प्रासंगिक शर्तों के सही निर्माण पर, यह कानून में हकदार नहीं है खंड 35.7 (बी) के मद्देनजर छूट/कटौती या समायोजन का दावा करने के लिए;

viii) उच्च न्यायालय द्वारा 4 फरवरी 2015 को इसी तरह स्थित एक अन्य रिट याचिकाकर्ता को जो राहत दी गई है, वह लागू होगी;

ix) 2019 में, प्रतिवादी ने सामान्य कानून के तहत सीमा की अवधि को दूर करने के उद्देश्य से संबंधित तीन आकलन वर्षों - FYs 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए तीन रिट याचिकाएं दायर कीं और इन्हें उच्च न्यायालय के सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा गलती से अनुमति दी गई है;

x) **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **भाईलाल भाई**[10] (**भाईलाल भाई**) और **सुगनमल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[11] (**सुगनमल**) में संविधान पीठ के निर्णयों में निर्धारित कानून अभी भी लागू है;

xi) उपर्युक्त निर्णयों में यह निर्णय दिया गया है कि प्रतिदाय के लिए कोई भी दावा केवल देय राशियों की वसूली के लिए वाद दायर करने हेतु सामान्य विधि के अधीन निर्धारित परिसीमा की अवधि के भीतर ही किया जा सकता है और उच्च न्यायालय को अपनी असाधारण रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 226 के अधीन किसी याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए

xii) उच्च न्यायालय के समक्ष किसी दलील के अभाव में, प्रतिवादी के विरुद्ध कानून में यह धारणा है कि विद्युत शुल्क से छूट/कटौती के रूप में दावा की गई राशि पहले ही अपने ग्राहकों को दे दी गई है। इसलिए, उच्च

---

[10] एआईआर 1964 एससी 1006

[11] एआईआर 1965 एससी 1740

न्यायालय द्वारा दिए गए समायोजन के परिणामस्वरूप प्रतिवादी को अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा। **मफतलाल उद्योग लिमिटेड** बनाम **भारत संघ**[12] ("**मफतलाल उद्योग**") में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया था;

xiii) बिहार अधिनियम, 1948 की धारा 9क के तहत अपील का एक वैकल्पिक और प्रभावोत्पादक सांविधिक उपाय एआईआर 1964 एससी 1006 के पास उपलब्ध था। 59 मूल्यांकन के आदेशों के खिलाफ प्रतिवादी, और इसलिए उच्च न्यायालय को असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लेने की अनुमति देने से इनकार कर देना चाहिए था; और

xiv) चूंकि प्रतिवादी की इकाई ने 17 अगस्त 2011 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, जबकि औद्योगिक नीति 2012 की है, इसलिए वचन पत्र के सिद्धांत को "प्रतिवादी के पक्ष में पीछे की ओर" नहीं बढ़ाया जा सकता है।

15. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से और उच्च न्यायालय के फैसले के समर्थन में इन प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, श्री देवाशीष भारूका, विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ करने का आग्रह किया:

i) 8 जनवरी 2015 से प्रभावी छूट अधिसूचना को भावी बनाने में राज्य सरकार का कार्य राज्य द्वारा अपनी औद्योगिक नीति 2012 में किए गए वादे के विपरीत है। उच्च न्यायालय ने वचनबद्धता के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए **मोतीलाल पदमपत** (सुप्रा), **कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड** (सुप्रा) और **मैनुएलसंस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड** (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णयों पर सही भरोसा किया है;

ii) जहां तक प्रथम प्रतिवादी द्वारा छूट के दावे का संबंध है,

(क)वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 की विवरणियों में छूट/कटौती के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता था। छूट अधिसूचना केवल 8 जनवरी 2015 को जारी की गई थी, और वह भी संभावित प्रभाव से;

---

[12] (1997) 5 एससीसी 536

(ख) पहले प्रतिवादी ने, तथ्य की बात के रूप में, केवल 8 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 की अवधि के लिए और वित्त वर्ष 2015-16 के लिए छूट/कटौती प्राप्त की है;

iii) जहां तक इस निवेदन का संबंध है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं शुरू करने में विलंब हुआ है:

(क) राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुमति याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष देरी का मुद्दा नहीं उठाया गया है;

(ख) एक बार जब उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका स्वीकार कर ली तो इस न्यायालय को इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि अकेले देरी की, खासकर जब उच्च न्यायालय का निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ हो;

(ग) रिट याचिका दायर करने में विलंब अपने आप में दावे को तब तक विफल नहीं कर सकता जब तक कि विपरीत पक्ष की स्थिति को इस प्रकार परिवतत न कर दिया गया हो कि इसे समय व्यतीत होने या रिट याचिकाकर्ता की निष्क्रियता के कारण वापस नहीं लिया जा सकता है। राज्य ने न तो अपनी स्थिति में बदलाव की वकालत की है और न ही तर्क दिया है;

(घ) यह एक ऐसा मामला है जहां उच्च न्यायालय से संपर्क करने में देरी के कारण विपरीत पक्ष को किसी भी कठिनाई के माध्यम से नहीं रखा गया है; और

iv) **भाईलाल भाई** (सुप्रा) और **सुगनमल** (सुप्रा) के फैसले अलग-अलग हैं क्योंकि वे अवैध रूप से एकत्र किए गए कर की वापसी की मांग करने वाली रिट याचिका से संबंधित हैं।

16. उपरोक्त आधारों पर, यह प्रतिवादी औद्योगिक नीति 2012 के खंड 32.10 में आयोजित के रूप में पांच साल की अवधि के लिए छूट के लाभ के हकदार है कि प्रस्तुत किया गया है.

17. प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि पांच साल की अवधि 17 अगस्त 2011 (वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख) या वित्त वर्ष 2012-13 (औद्योगिक नीति 2012 के खंड 35.7 (बी) के अनुसार) या 8 जनवरी 2015 (अधिसूचना की तारीख) से शुरू हो सकती है।

एच. विश्लेषण

18. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अब विचार किया जाएगा।

एच 1. ए नीतिगत वचनबद्धताओं के उल्लंघन में एक राज्य।

19. औद्योगिक नीति 2012 पूर्व औद्योगिक नीति को संदर्भित करती है, जिसे झारखंड राज्य के गठन के बाद 2001 में तैयार किया गया था। नीति में कहा गया है कि "नीति अवधि के दौरान औद्योगीकरण में काफी प्रगति हासिल की गई है"। फिर भी, खंड 1.8 के अनुसार, "विकास के मौजूदा स्तर को बनाए रखने और विकास की बेहतर गति प्राप्त करने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने" की आवश्यकता है। खंड 1.9 इस तथ्य पर ध्यान देता है कि "आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण औद्योगीकरण के माहौल में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है"। नीति दस्तावेज में खंड 1.12 में कहा गया है कि इसका उद्देश्य "निवेश को अधिकतम करने के लिए उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाना है"

> "1.12. वर्तमान नीति का उद्देश्य विशेष रूप से खनिज और प्राकृतिक संसाधन आधारित उद्योगों, एमएसएमई, बुनियादी ढांचे के विकास और व्यवहार्य बीमार इकाइयों के पुनर्वास में निवेश को अधिकतम करने के लिए उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाना है। यहां उद्देश्य राज्य भर में उद्योग स्थापित करके, राजस्व पैदा करके और रोजगार पैदा करके राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य संवर्धन को अधिकतम करना है।
>
> खंड 1.13 में यह निर्धारित किया गया है कि नीति का मसौदा हितधारकों के साथ गहन बातचीत के बाद और उनके विचारों को समायोजित करने के लिए तैयार किया गया था। यह आशा की गई थी कि इस नीति के कार्यान्वयन से राज्य का औद्योगिकीकरण सुकर होगा, रोजगार का सृजन होगा और इसके समग्र विकास में वृद्धि होगी।

20. नीति के एक अभिन्न घटक के रूप में, खंड 32.10 में स्व-उपभोग या कैप्टिव उपयोग के लिए कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने वाली नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के लिए पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क के 50 प्रतिशत के भुगतान से छूट देने की परिकल्पना की गई है। क्लॉज 35.7 (बी) के तहत, पात्रता उत्पादन की तारीख के बाद वित्तीय वर्ष से होगी। राज्य सरकार पांच साल की पूरी अवधि में पात्र इकाइयों को लाभ सुरक्षित करने के लिए नीति को तुरंत लागू करने की आवश्यकता से अवगत थी। इस आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, खंड 38 (बी) में परिकल्पना की गई है कि नीति की शर्तों को लागू करने के लिए इसके विविध विभागों द्वारा अधिसूचनाएं एक महीने की अवधि के भीतर जारी की जाएंगी।

21. झारखंड राज्य की औद्योगिक नीति 2012 द्वारा अपेक्षित तत्परता को इसके प्रशासनिक तंत्र में प्रतिध्वनि नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने इसे नौकरशाही सुस्ती का मामला बताया है। पहले सिद्धांत के रूप में, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब बिहार अधिनियम 1948 जैसा कोई क़ानून, राज्य को अपने प्रावधानों से छूट देने का अधिकार देता है, तो राज्य के पास यह निर्धारित करने का विवेक है कि किस तारीख से और किस अवधि में छूट लागू होगी। कोई व्यक्ति या संस्था राज्य को छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना जारी करने या उन शर्तों पर जोर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है जिन पर सरकार ऐसा करती है। क्या छूट जारी की जानी चाहिए और यदि हां, तो छूट की शर्तें राज्य द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। लेकिन यह मामला उस सिद्धांत पर आधारित नहीं है और न ही प्रतिवादी के दावे के लिए उच्च न्यायालय को इससे प्रस्थान करने की आवश्यकता है। औद्योगिक नीति 2012 में एक अभ्यावेदन निहित था की छूट/कटौती दी जाएगी। इसने एक अभ्यावेदन दिया कि एक महीने में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। ये ळाराखंड राज्य द्वारा की गई गंभीर वचनबद्धताएं थीं। जो रह गया वह एक अधिसूचना जारी करके उनका कार्यान्वयन था, जिसे एक महीने के भीतर किया जाना था। राज्य सरकार स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार लागू करने और कार्य करने का इरादा रखती थी। अंतत इसने एक अधिसूचना जारी

की। लेकिन औद्योगिक नीति 2012 के तहत परिकल्पित एक महीने की अवधि के लगभग तीन साल तक खिंचने के बाद, 8 जनवरी 2015 को इसने ऐसा किया।

22. अब समय आ गया है कि राज्य सरकार प्रशासनिक सुस्ती के संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर ध्यान दे। यदि औद्योगिक नीति तैयार करने का उद्देश्य निवेश, रोजगार और विकास को प्रोत्साहित करना है, तो राज्य तंत्र की प्रशासनिक सुस्ती स्पष्ट रूप से एक कारक है जो उद्यमशीलता को हतोत्साहित करेगी। नीति दस्तावेज में एक गंभीर प्रतिनिधित्व किया गया था। इसने न केवल नई इकाइयों को बल्कि मौजूदा इकाइयों को भी विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट/कटौती प्रदान करने पर विचार किया, जिन्होंने कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित किए थे या स्थापित करेंगे। वर्तमान मामले में, राज्य ने अन्य बातों के *साथ-साथ* उत्पादन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए छूट की पात्रता के खंड 32.10 और 35.7 (बी) के संदर्भ में एक गंभीर प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, यह भी खंड 38 (बी) में विचार किया गया है कि एक महीने के भीतर एक अनुवर्ती छूट अधिसूचना जारी की जाएगी। एक महीने की वह अवधि इस परिणाम के साथ अंतहीन रूप से खिंच गई कि छूट देने का उद्देश्य और उद्देश्य वस्तुतः पराजित हो जाएगा। इसका परिणाम यह हुआ कि जब देर से ही सही, राज्य सरकार ने 8 जनवरी 2015 को बिहार अधिनियम 1948 की धारा 9 के तहत एक अधिसूचना जारी की, तो यह भावी था। परिणामस्वरूप, जब तक छूट अधिसूचना जारी की गई, तब तक औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार छूट का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया था।

23. राज्य सरकार स्पष्ट रूप से छूट देने के लिए इच्छुक थी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां जनहित की अत्यधिक आवश्यकता के कारण, राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति 2012 में निहित प्रतिनिधित्व को ओवरराइड करने का निर्णय लिया। इसके विपरीत, इसने फिट और शुरुआत में *प्रतिनिधित्व* को लागू करने की मांग की। सबसे पहले, अधिसूचना जारी होने में तीन साल की देरी हुई। दूसरे, अधिसूचना को भावी बनाकर, इसने प्रतिवादी जैसी इकाइयों को छूट के पूर्ण लाभ से वंचित कर दिया, जिसकी मूल रूप से औद्योगिक नीति 2012 के संदर्भ में परिकल्पना की गई थी

एच.2. मोतीलाल पदमपत पर भवन

24. इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने औचित्य के साथ, इस न्यायालय के दो निर्णयों का विज्ञापन किया है। **कल्याणपुर सीमेंट** (सुप्रा) में बिहार राज्य में 1995 में एक औद्योगिक नीति अधिसूचित की गई थी। नीति में निगरानी और समीक्षा के लिए एक प्रावधान था और यह परिकल्पना की गई थी कि सभी विभाग और संगठन एक महीने के भीतर नीति को प्रभावी करने के लिए एक अनुवर्ती अधिसूचना जारी करेंगे। यह वर्तमान मामले में नीति के खंड 38 (बी) के समान था। औद्योगिक नीति, जो 31 अगस्त, 2000 को व्यपगत हो गई, को प्रभावी बनाने के लिए बिहार राज्य द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। इकाई द्वारा बिक्री कर छूट के दावे को राज्य सरकार ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसने एक बीमार औद्योगिक इकाई को प्रोत्साहन नहीं देने का फैसला किया था। इस न्यायालय के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान एक अनुवर्ती अधिसूचना जारी की गई थी। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति एसएस निज्जर के माध्यम से बोलते हुए कहा:

> "85. भले ही हमें सबमिशन स्वीकार करना हो ... कि खंड 24 में निहित प्रावधान अनिवार्य थे, अधिसूचना जारी करने के लिए एक महीने का समय केवल उचित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता था। यह अकल्पनीय है कि अनुवर्ती अधिसूचना जारी करने में सरकार को तीन वर्ष लग सकते थे। हमारा विचार है कि औद्योगिक नीति, 1990 1995 के प्रवर्तन की उचित अवधि के भीतर आवश्यक अधिसूचना जारी करने में अपीलकर्ताओं की विफलता ने 6-1-2001 और 5-3-2001 के निर्णयों को पूरी तरह से मनमाना बना दिया है। अपीलकर्ता को कंपनी के न्यायसंगत और वैध दावे को हराने के लिए अपनी नीति को लागू करने में अपनी खामियों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी कारण से हम अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुतियों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि कंपनी को कोई राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि पॉलिसी 31-8-2000 को समाप्त हो गई है। इस तरह के सबमिशन को स्वीकार

करना औद्योगिक नीति, 1995 के खंड 24 में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना जारी नहीं करने में अपीलकर्ता की पूरी तरह से मनमानी कार्रवाई के लिए एक औचित्य देना होगा।

25. **मैनुएलसन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य** (सुप्रा), निर्णय में। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन के माध्यम से बोलते हुए, न्यायालय को केरल सरकार की 11 जुलाई 1986 की एक अधिसूचना का अर्थ लगाना पड़ा, जिससे पर्यटन प्रचार गतिविधियों में लगे लोग समय-समय पर औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली रियायतों/प्रोत्साहनों के लिए स्वचालित रूप से पात्र हो गए। केरल भवन कर अधिनियम 1975 में संशोधन 6 नवंबर से 1986 में किए गए वादे के अनुसार छूट दे रहा है और संशोधन 1 मार्च 1993 से प्रभावी रूप से हटा दिया गया था। **मोतीलाल पदमपत** (सुप्रा) में इस न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने कहा:

"3... इस तरह की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न करना स्पष्ट रूप से मोतीलाल पदमपत [मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1979) 2 एससीसी 409: 1979 एससीसी (टैक्स) 144: (1979) 2 एससीआर 641] और नेस्ले [पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड] में इस न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में वचनपत्र के सिद्धांत के आवेदन के कारण दूषित है। यह इस कारण से है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग न करना अपने आप में एक मनमाना कार्य है जो प्रासंगिक तथ्यों पर दिमाग न लगाने से दूषित होता है, अर्थात्, तथ्य यह है कि 11-7-1986 के एक सरकारी आदेश में विशेष रूप से भवन कर से छूट का प्रावधान किया गया था यदि उक्त सरकारी आदेश में किए गए अभ्यावेदन के अनुसार केरल राज्य में होटल स्थापित किए जाने थे। केरल भवन कर अधिनियम, 1975 में संशोधन करने के लिए कोई भी परमादेश विधायिका को जारी नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके लिए न्यायपालिका को शक्तियों के पृथक्करण की संवैधानिक योजना के तहत एक निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने में शामिल किया जाएगा। हालांकि, तथ्यों पर, हम पाते हैं कि धारा 3-

ए, वास्तव में, 11-7-1986 के सरकारी आदेश द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व को प्रभावी करने के लिए 6-11-1990 को केरल भवन कर अधिनियम, 1975 में उपयुक्त संशोधन करके केरल विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। हम पाते हैं कि उक्त प्रावधान क़ानून की किताब पर जारी रहा और केवल 1-3-1993 से हटा दिया गया। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि 6-11-1990 से 1-3-1993 तक, भवन कर से छूट देने की शक्ति वैधानिक रूप से सरकार को धारा 3-ए द्वारा प्रदान की गई थी। और हमने देखा है कि धारा 3-ए को पेश करने के उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त धारा को 11-7-1986 के सरकारी आदेश में निहित वादों में से एक को पूरा करने के लिए पेश किया गया था। हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं ने 11-7-1986 के उक्त सरकारी आदेश पर भरोसा करते हुए, वास्तव में, 1991 तक एक होटल भवन का निर्माण किया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 3-ए के तहत अधिसूचना जारी न करना सरकार का एक मनमाना कार्य था, जिसे वचनबद्धता के सिद्धांत के आवेदन द्वारा ठीक किया जाना चाहिए, जैसा कि हमारे द्वारा यहां ऊपर कहा गया है। अधिसूचना जारी न करने का मंत्रिस्तरीय कार्य संभवतः अपीलकर्ताओं को उक्त सिद्धांत के तहत राहत मिलने के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि सरकार की ओर से अपने वादे को पूरा किए बिना दूर होना अनुचित होगा।

H.3 वचन पत्र - उत्पत्ति और विकास

26. उच्च न्यायालय के समक्ष, झारखंड राज्य ने इस आधार पर अपनी कार्रवाई को बनाए रखने की मांग की कि हालांकि धारा 9 के तहत अनुवर्ती अधिसूचना 8 जनवरी 2015 को जारी की गई थी, अधिसूचना जारी करने के लिए कोई बाहरी सीमा निर्धारित नहीं की गई थी और अधिसूचना को पहले की तारीख से लागू करने या नीति का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी की ओर से कोई निहित अधिकार नहीं था। एक अनुवर्ती सूचना। **कल्याणपुर सीमेंट** (सुप्रा) में निर्णय को इस आधार पर अलग करने की मांग की गई थी कि उस मामले में पॉलिसी समाप्त होने

तक कोई अनुवर्ती अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। संक्षेप में, आपत्ति यह थी कि रिट याचिकाकर्ता - यहां प्रतिवादी - के पास यह दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं था कि एक अनुवर्ती अधिसूचना जारी की जानी चाहिए और यह कि *वचनबद्धता* का सिद्धांत तथ्यों में लागू नहीं होगा।

27. वर्तमान मामले में वचन पत्र के विबन्धन से संबंधित विवादों का विश्लेषण करने के लिए, सिद्धांत की उत्पत्ति और इसके आवेदन के विकास पर चर्चा करना आवश्यक है। आम कानून विभिन्न प्रकार के न्यायसंगत एस्टोपेल को मान्यता देता है, जिनमें से एक वचन पत्र है। **क्रैब बनाम अरुण डीसी**[13] में, लॉर्ड डेनिंग ने कोर्ट ऑफ अपील के लिए बोलते हुए, में *वचनबद्धता* की उत्पत्ति का पता लगाया, और देखा:

> "इस मालिकाना वचनपत्र का आधार - जैसा कि वास्तव में वचनबद्धता का है - अंतर्वस्तु का क्षेप है। सख्त कानून की कठोरता को कम करने के लिए, अंतर्वस्तु सही है। शुरुआती मामलों ने इसे "वचनपत्र" के रूप में नहीं बोला। यदि मैं इसका विस्तार कर सकता हूं, तो लॉर्ड केर्न्स ने कहा: "यह पहला सिद्धांत है जिस पर सभी न्यायालयें आगे बढ़ते हैं", कि यह किसी व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों पर जोर देने से रोकेगा - चाहे वह किसी अनुबंध के तहत उत्पन्न हो या उसके शीर्षक विलेख पर, या क़ानून द्वारा - जब उसके लिए ऐसा करना अन्यायपूर्ण होगा पक्षों के बीच हुए लेन-देन के संबंध में।

28. वचनबद्धता के सिद्धांत की आवश्यकताओं को भी संविदा[14] ("**चिट्टी**") पर चिट्टी में तैयार किया गया है:

> "4.086. न्यायसंगत सिद्धांत के संचालन के लिए पार्टियों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को जन्म देने वाला एक कानूनी संबंध होना चाहिए; एक वादा या एक पार्टी द्वारा एक प्रतिनिधित्व कि वह लागू नहीं करेगा दूसरे के खिलाफ उस रिश्ते से उत्पन्न होने वाले उसके सख्त कानूनी अधिकार; पूर्व पार्टी की ओर से एक इरादा है कि उत्तरार्द्ध प्रतिनिधित्व पर भरोसा करेगा; और बाद वाली पार्टी द्वारा इस तरह की

[13] [1976] 1 चौधरी 179 (अपील की अदालत).

[14] ह्यूग बीले, अनुबंधों पर चिट्टी (32 वां संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल 2017)

निर्भरता। यहां तक कि अगर इन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, तो सिद्धांत के संचालन को बाहर रखा जा सकता है यदि यह है, फिर भी, पहले पक्ष के लिए अपने वादे पर वापस जाने के लिए "असमान" नहीं है। सिद्धांत आमतौर पर संविदात्मक अधिकारों को लागू नहीं करने के वादों पर लागू होता है, लेकिन यह कुछ अन्य संबंधों तक भी फैला हुआ है।

4.088..... सिद्धांत भी लागू हो सकता है जहां अधिकारों और सहसंबंधी कर्तव्यों को जन्म देने वाला संबंध गैर-संविदात्मक है: उदाहरण के लिए विनिमय के बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी के निदेशक पर क़ानून द्वारा लगाए गए दायित्व के प्रवर्तन को रोकने के लिए, जिस पर कंपनी का नाम सही ढंग से नहीं दिया गया है; या एक आदमी को एक महिला को बाहर निकालने से रोकने के लिए, जिसके साथ वह परिवार के घर से सहवास कर रहा है।

चिट्टी (सुप्रा) स्पष्ट करता है कि कानूनी संबंध के अभाव में भी *वचनबद्धता के सिद्धांत* को लागू किया जा सकता है। हालांकि, यह तर्क दिया जाता है कि यह सिद्धांत का गलत अनुप्रयोग होगा क्योंकि यह पार्टियों के बीच नए अधिकारों को जन्म देता है, जब सिद्धांत का इरादा पहले से मौजूद अधिकारों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित करना है:

"4.089. वास्तव में, यह सुझाव दिया गया है कि सिद्धांत लागू हो सकता है, जहां वादा या प्रतिनिधित्व करने से पहले, पार्टियों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को जन्म देने वाला कोई कानूनी संबंध नहीं है, या जहां उनके बीच केवल एक ख्यात अनुबंध है: उदाहरण के लिए जहां वादा करने वाले को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि एक अनुबंध जिसमें उसने निस्संदेह प्रवेश किया था, उसके और वादा करने वाले के बीच था, जब वास्तव में यह वादा करने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के बीच था। लेकिन यह प्रस्तुत किया गया है कि ये सुझाव सिद्धांत की प्रकृति को गलत मानते हैं, जो कि वादा करने वाले के खिलाफ पहले से मौजूद अधिकारों के प्रचारक द्वारा प्रवर्तन को प्रतिबंधित करना है। इस तरह के अधिकार केवल वादा या प्रतिनिधित्व करने से पहले इन पक्षों के बीच मौजूद कानूनी संबंध से उत्पन्न हो सकते हैं। सिद्धांत को लागू करने के लिए जहां ऐसा कोई संबंध नहीं था,

नियम का उल्लंघन होगा (नीचे पैरा 4-099 में चर्चा की जाएगी) कि सिद्धांत कोई नया अधिकार नहीं बनाता है।

29. आम तौर पर अंग्रेजी कानून के तहत बोलते हुए, न्यायिक निर्णयों ने अतीत में यह माना है कि वचन पत्र के सिद्धांत को 'तलवार' के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ताकि किसी भी विचार की कमी वाले वादे के प्रवर्तन के लिए कार्रवाई का कारण बन सके। उन निर्णयों में इसका उपयोग एक 'ढाल' के रूप में सीमित किया गया है, जहां वादा करने वाले को अपने सख्त कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन का दावा करने से रोक दिया जाता है, जब ऐसे अधिकारों को निलंबित करने के लिए शब्दों या आचरण द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। **कॉम्बे बनाम कॉम्बे**[15] **("कॉम्बे")** में, अपील की अदालत ने माना कि विचार कार्रवाई के कारण का एक अनिवार्य तत्व है:

> "यह [वचन पत्र] कार्रवाई के कारण का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कार्रवाई का कारण नहीं है।
>
> सिद्धांत [वचन पत्र] अपने आप में कार्रवाई का कारण देने के रूप में अकेला नहीं खड़ा होता है, यह कभी भी विचार की आवश्यकता को दूर नहीं कर सकता है जब कि कार्रवाई के कारण का एक अनिवार्य हिस्सा है। विचार का सिद्धांत एक साइड-विंड द्वारा उखाड़ फेंकने के लिए बहुत मजबूती से तय किया गया है। ''

30. अंग्रेजी कानून के भीतर भी, **कॉम्बे** (सुप्रा) में निर्धारित नियम के आवेदन को असंगत[16] देखा गया है। नियम के दायरे पर इस आधार पर भी संदेह किया गया है कि इसे व्यापक रूप से बनाया गया है[17]। इसलिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा एक निश्चित घोषणा के अभाव में कि वचन पत्र कार्रवाई का कारण हो सकता है, निश्चितता के साथ यह बताने में

---

[15] [1951] 2 के.बी.

[16] **वायवर्न डेवलपमेंट, आरई,** [1974] 1 डब्ल्यूएलआर 1097 सुसान एम. मॉर्गन में उद्धृत, "ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में वचन पत्र के सिद्धांत का तुलनात्मक विश्लेषण", (1985) 15 मेलबोर्न यूनिवर्सिटी लॉ रिव्यू 134, 139-141।

[17] **टंगस्टन इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड** बनाम **टूल मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड**, [1955] 1 डब्ल्यूएलआर 761 में, लॉर्ड साइमंड्स कहते हैं, "मैं इस सदन के अधिकार को सिद्धांत के बयान के लिए उधार नहीं देना चाहता हूं जो कॉम्बे बनाम भारत संघ और अन्य में पाया जाना है। कॉम्बे और अच्छी तरह से बहुत व्यापक रूप से कहा जा सकता है"।

एक कठिनाई व्यक्त की गई थी कि अंग्रेजी कानून वचनपत्र को 'तलवार'[18] के बजाय 'ढाल' के रूप में मानने के पारंपरिक दृष्टिकोण से विकसित हुआ है। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका[19] और ऑस्ट्रेलिया[20] में कानून इस संबंध में कम प्रतिबंधात्मक है।

31. भारत, जैसा कि हम शीघ्र ही खोज करेंगे, ने सिद्धांत का अधिक विस्तृत विवरण अपनाया। तुलनात्मक कानून उन देशों को सक्षम बनाता है जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार से एक सिद्धांत को लागू करते हैं ताकि उन्हें पीछे की दृष्टि का लाभ मिल सके। इस न्यायालय ने एक वादे पर भरोसा करने वाले पक्ष के साथ किए जा रहे अन्याय को दूर करने के लिए वचनबद्धता के सिद्धांत की एक विस्तृत व्याख्या की है। **मोतीलाल पदमपत** (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने *वचनबद्धता* को इक्विटी में एक सिद्धांत के रूप में देखा, जो विचार के सिद्धांत से बाधित नहीं था जैसा कि अंग्रेजी कानून के तहत मामला था। इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति पीएन भगवती (जैसा कि वह तब थे) के माध्यम से बोलते हुए, इस प्रकार कहा:

> "12........ उस सामान्य अपमान को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए प्रतिष्ठित न्यायविदों द्वारा विचार का सिद्धांत दिया गया है, हमें इस सिद्धांत को हमले या क्षरण के खिलाफ प्रोजेक्ट करने के लिए अनावश्यक रूप से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और न ही इसे वचनबद्धता की इक्विटी के पूर्ण विकास को बौना या बाधित करने या न्याय उपकरण के रूप में इसकी परिचालन प्रभावकारिता को बाधित या कम करने की अनुमति नहीं है। अन्याय को रोकना... हम कोई वैध कारण नहीं देखते हैं कि वचनबद्धता को कार्रवाई का कारण खोजने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए, जहां इक्विटी को संतुष्ट करने के लिए, ऐसा करना आवश्यक है। ''

H.4 विबन्धन से अपेक्षा तक

32. अंग्रेजी कानून के तहत, वचनबद्धता का सिद्धांत वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत के समानांतर विकसित हुआ है। वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत सरकारी व्यवहार

---

[18] **बेयर्ड टेक्सटाइल्स होल्डिंग्स लिमिटेड** बनाम **मार्क्स एंड स्पेंसर पीएलसी**, [2002] 1 ऑल ईआर (कॉम) 737 में, कोर्ट ऑफ अपील ने कहा कि "हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कानून विकसित या सही होने तक दावे [एस्टोपेल] के सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है"।

[19] अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट, रिस्टेटमेंट ऑफ द लॉ (2 डी), कॉन्ट्रैक्ट्स (1981), पैरा 90। 20 वाल्टन स्टोर्स (इंटरस्टेट) लिमिटेड बनाम माहेर, (1988) 164 सीएलआर 387

[20] वाल्टन स्टोर्स (इंटरस्टेट) लिमिटेड बनाम माहेर, (1988) 164 सीएलआर 387

में निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह खेल में आता है यदि कोई सार्वजनिक निकाय किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वे एक महत्वपूर्ण लाभ के प्राप्तकर्ता होंगे। वास्तविक वैध अपेक्षा के सिद्धांत को **आर बनाम उत्तर और पूर्व डेवोन स्वास्थ्य प्राधिकरण, एक्स पी कफलान**[21] में निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है:

> "55.... लेकिन उनकी जायज उम्मीद क्या थी? जहां इस बारे में कोई विवाद है, विवाद का निर्धारण अदालत द्वारा किया जाना है, जैसा कि इन रे फाइंडले में हुआ था। इसमें किए गए वादे या प्रतिनिधित्व की सटीक शर्तों की विस्तृत जांच शामिल हो सकती है, जिन परिस्थितियों में वादा किया गया था और वैधानिक या अन्य विवेक की प्रकृति।
>
> (महत्त्व सन्निविष्ट)
>
> 56....जहां अदालत मानती है कि एक वैध वादे या अभ्यास ने एक लाभ की वैध अपेक्षा को प्रेरित किया है जो वास्तविक है, न कि केवल प्रक्रियात्मक, अधिकार अब स्थापित करता है कि यहां भी अदालत एक उचित मामले में तय करेगी कि क्या उम्मीद को विफल करना इतना अनुचित है कि एक नया और अलग रास्ता अपनाना शक्ति का दुरुपयोग होगा। यहां, एक बार उम्मीद की वैधता स्थापित हो जाने के बाद, अदालत के पास नीति के परिवर्तन के लिए भरोसा किए गए किसी भी अधिभावी ब्याज के खिलाफ निष्पक्षता की आवश्यकताओं को तौलने का कार्य होगा।
>
> (महत्त्व सन्निविष्ट)

33. अंग्रेजी कानून के तहत, वैध अपेक्षा का सिद्धांत शुरू में सार्वजनिक कानून के संदर्भ में निजी कानून में पाए जाने वाले वचन पत्र के सिद्धांत के सादृश्य के रूप में विकसित हुआ। हालांकि, तब से, अंग्रेजी कानून ने क्रमशः निजी कानून और सार्वजनिक कानून के तहत अलग-अलग उपायों के रूप में वचन पत्र और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों के बीच अंतर किया है। *डी स्मिथ* की न्यायिक समीक्षा[22] वैध

---

[21] [2001] क्यूबी 213

[22] हैरी वूल्फ और अन्य, डी स्मिथ की न्यायिक समीक्षा (8 वां संस्करण, थॉमसन रॉयटर्स 2018)

अपेक्षा के सिद्धांत के सार्वजनिक कानून दृष्टिकोण और वचन पत्र के सिद्धांत के निजी कानून दृष्टिकोण के बीच अंतर को नोट करता है:

> "[डी] इसके विपरीत *[रूटकिन बनाम केंट सीसी,* (1981) 1 डब्ल्यूएलआर 1186 (सीए); *आर बनाम जॉकी क्लब एक्स पी रैम रेसकोर्स लिमिटेड,* [1993] एसी 380 (एचएल); *आर बनाम आईआरसी एक्स पी कैमैक कॉर्प, (*1990) 1 डब्ल्यूएलआर 191 (सीए)], किसी व्यक्ति के लिए यह आम तौर पर आवश्यक नहीं है कि उसने अपनी स्थिति बदल दी हो या वैध अपेक्षा के धारक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए अपने नुकसान के लिए काम किया हो [कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य पदार्थों के लिए *आर बनाम मंत्रालय एक्स पी हम्बल फिशरीज (ऑफशोर) लिमिटेड,* (1995) 2 सभी ईआर 714 (क्यूबी)]। । एस्टोपेल के क्षेत्र से निजी कानून की उपमाएं, हमने देखी हैं, सीमित प्रासंगिकता की जहां एक सार्वजनिक कानून सिद्धांत के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को अपने उपक्रमों का सम्मान करने और कानूनी निश्चितता का सम्मान करने की आवश्यकता होती है, भले ही संबंधित व्यक्ति द्वारा नुकसान उठाया गया हो *[साइमन एट्रिल, 'सार्वजनिक कानून में एस्टोपेल का अंत?' (2003) 62 कैम्ब्रिज लॉ जर्नल 3]।*
>
> (महत्त्व सन्निविष्ट)

34. अंग्रेजी कानून के तहत वचनबद्धता और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों के बीच एक और अंतर यह है कि बाद के 22 हैरी वूल्फ और अन्य, डी स्मिथ की न्यायिक समीक्षा (8 वां संस्करण, थॉमसन रॉयटर्स 2018)। कार्रवाई का कारण बन सकता है[23]. वैध अपेक्षा के सिद्धांत का दायरा वचनबद्धता की तुलना में व्यापक है क्योंकि यह न केवल एक सार्वजनिक निकाय द्वारा किए गए वादे को ध्यान में रखता है, बल्कि आधिकारिक अभ्यास भी करता है[24]। इसके अलावा, वचनबद्धता के सिद्धांत के तहत, वादे पर रखी गई निर्भरता के कारण किसी पार्टी को होने वाली हानि दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। यद्यपि आम तौर पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिज्ञाकर्ता ने वादे पर भरोसा करके अपनी स्थिति बदल दी है,

---

[23] रेबेका विलियम्स, "वैध उम्मीदों के कई सिद्धांत", (2016) 132 (अक्टूबर) कानून त्रैमासिक समीक्षा 639, 645।

[24] पूर्व नोट 19 पैरा 4-095 पर। 25[2002] 1 डब्ल्यूएलआर 237

यह तथ्य कि प्रतिज्ञाकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है, यह धारण करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है कि वादा करने वाले के लिए अपने वादे से पीछे हटना "असमान" नहीं होगा। **रेजिना (बीबी) बनाम न्यूहैम लंदन बोरो काउंसिल**[25] में, अपील की अदालत ने आयोजित किया:

> "55 वर्तमान मामला ठोस हानि के बिना निर्भरता में से एक है। हम इस वाक्यांश का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि नैतिक हानि है, जिसे हल्के ढंग से खारिज नहीं किया जाना चाहिए, लंबे समय तक निराशा में जो हुआ है; और संभावना के विक्षेपण में संभावित हानि, एक शरणार्थी परिवार के लिए, यूनाइटेड किंगडम में कहीं बसने की शुरुआत में तलाश करना जहां सुरक्षित आवास आना कम कठिन था। <u>हमारे विचार में ये चीजें सार्वजनिक कानून में मायने रखती हैं, भले ही उन्हें निजी कानून में एक एस्टोपेल या कार्रवाई योग्य गलत बयानी न मिले, क्योंकि वे निष्पक्षता और निष्पक्षता के माध्यम से सत्ता के संभावित दुरुपयोग के लिए जाते हैं। वैध अपेक्षा की अवहेलना करना क्योंकि कोई ठोस नुकसान नहीं दिखाया जा सकता है, समाज में सबसे कमजोर को एक विशेष नुकसान में रखना होगा। इसका मतलब यह होगा कि जिनके पास कुछ आधिकारिक अभ्यास या वादे पर निर्भरता में इसका प्रयोग करने का विकल्प और साधन है, वे उन लोगों के लिए दुर्गम कानूनी पैर प्राप्त करेंगे, जिनके पास भागने के किसी भी साधन की कमी है, बस उन पर अपना भरोसा रखने के लिए मजबूर हैं जो उनका प्रतिनिधित्व किया गया है।</u>
>
> (महत्त्व सन्निविष्ट)

35. नतीजतन, जबकि निजी कानून में *वचन पत्र* के सिद्धांत का आधार दो पक्षों के बीच किया गया वादा है, सार्वजनिक कानून में वैध अपेक्षा के सिद्धांत का आधार निष्पक्षता और गैर-मनमानी के सिद्धांतों पर आधारित है आचरण सार्वजनिक प्राधिकरणों के यह सुझाव देने के लिए नहीं है कि *वचनबद्धता* के सिद्धांत का उन परिस्थितियों में कोई अनुप्रयोग नहीं है जब एक राज्य इकाई ने किसी अन्य निजी पार्टी के साथ एक निजी अनुबंध में प्रवेश किया है। बल्कि, अंग्रेजी कानून में, यह

[25][2002] 1 डब्ल्यूएलआर 237

उन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है जब राज्य ने अपने *सार्वजनिक कार्यों* को आगे बढ़ाने में एक निजी पार्टी को प्रतिनिधित्व दिया है[26]।

H.5. भारतीय कानून और वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत

36. भारतीय कानून के तहत, अक्सर *वचनबद्धता* और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों के बीच टकराव होता है। जैन और जैन के प्रसिद्ध ग्रंथ,*प्रशासनिक कानून के सिद्धांत* [27] में इसका वर्णन किया गया है:

> "कभी-कभी, अभिव्यक्ति 'वैध अपेक्षा' और 'वचनबद्धता' का परस्पर उपयोग किया जाता है, लेकिन यह एक सही उपयोग नहीं है क्योंकि 'वैध अपेक्षा' एक अवधारणा है जो 'वचनबद्धता' की तुलना में दायरे में बहुत व्यापक है।
> हालांकि, प्रासंगिक भारतीय मामलों को पढ़ने से विचारों में कुछ भ्रम दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सिद्धांत की प्रकृति और दायरे के संबंध में न्यायिक सोच अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है।

कभी-कभी, इसे केवल एक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया गया है; कभी-कभी, इसे एक दूसरे के स्थान पर वचनबद्धता के रूप में माना जाता है। हालाँकि, ये दोनों विचार गलत हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वैध अपेक्षा एक मूल सिद्धांत भी है और इसमें वचनबद्धता की तुलना में बहुत व्यापक गुंजाइश है.

पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने "वैध अपेक्षा के सिद्धांत के संबंध में टिप्पणी की है मूल अर्थों में वैध अपेक्षा के सिद्धांत को हमारे कानून के भाग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और यह कि निर्णय लेने वाले को सामान्यत पिछले अभ्यास या पिछले आचरण के आधार पर अपेक्षा के संबंध में अपने अभ्यावेदन को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य किया जा सकता है जब तक कि कुछ अधिभावी जनहित उस रास्ते में न आ जाए जिस पर निर्भरता को रखा गया हो उक्त अभ्यावेदन और प्रतिनिधि को इस प्रकार नुकसान उठाना पड़ा होगा।''

यह सुझाव दिया जाता है कि वैध अपेक्षा के सिद्धांत का यह सूत्रीकरण सही नहीं है क्योंकि यह "वैध अपेक्षा" को व्यावहारिक रूप से वचन पत्र का पर्याय बनाता है।

---

[26] निकोलस बामफोर्थ, "वैध अपेक्षा और एस्टोपेल" (1998) 3 जज रेव 196

[27] एमपी जैन और एसएन जैन, प्रशासनिक कानून के सिद्धांत (7 वां संस्करण, ईबीसी 2013)

प्राधिकरण के आचरण से वैध अपेक्षा उत्पन्न हो सकती है; उद्देश्य के लिए एक वादा हमेशा आवश्यक नहीं होता है।

37. जबकि इस सैद्धांतिक भ्रम में कानून को अस्पष्ट बनाने का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है, नागरिक पीड़ित रहे हैं। सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन को ईमानदार मानकों पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि नागरिक राज्य में अपने विश्वास के आधार पर अपना जीवन जीना जारी रखते हैं। वाणिज्यिक दुनिया में भी, व्यवसाय के मामलों की योजना बनाने के लिए निश्चितता और निरंतरता आवश्यक है। जब सार्वजनिक प्राधिकरण इस विफलता के लिए नागरिकों को पर्याप्त कारण प्रदान किए बिना उनके अभ्यावेदन का पालन करने में विफल रहते हैं, तो यह राज्य में नागरिकों द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास का उल्लंघन करता है। निवेश और व्यापार के लिए एक व्यापार अनुकूल माहौल की पीढ़ी उस विश्वास से वातानुकूलित होती है जिसे सरकार द्वारा उत्पन्न अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार में दोहराया जा सकता है। प्रोफेसर जैन और देशपांडे इस सैद्धांतिक भ्रम के परिणामों को निम्नलिखित शब्दों में चित्रित करते हैं:

"इस प्रकार, भारत में, वैध अपेक्षाओं का लक्षण वर्णन ब्रिटेन जैसे न्यायालयों की तुलना में कमजोर स्तर पर है, जहां अदालतें अब एलई [वैध अपेक्षाओं] और शक्ति के दुरुपयोग जैसे सिद्धांतों के विकास के प्रकाश में एस्टोपेल की धारणा को अंतर्निहित नैतिक मूल्यों को अवशोषित करने के लिए सार्वजनिक कानून की क्षमता को पहचानने के लिए तैयार हैं। यदि भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजी विधि की सीमाओं से वचनबद्धता की धारणा को बदलने में अपनी रचनात्मकता दिखाई है, तो वह इस तर्क के साथ खड़ा नहीं होता है कि उसे नीतियों और दीर्घकालिक प्रथाओं से प्रशासनिक प्राधिकारियों के पुनर्मूल्यांकन की न्यायिक समीक्षा के लिए एलई के सिद्धांत को स्पष्ट और विकसित क्यों नहीं करना चाहिए। यदि एलई की ऐसी धारणा को अपनाया जाता है, तो न केवल न्यायालय वचनबद्धता और वैध अपेक्षा के बीच कृत्रिम पदानुक्रम को समाप्त करने में सक्षम होगा, बल्कि, यह प्रशासनिक लेखक को भी धारण करने में सक्षम होगा एक मजबूत और राजसी निहाई पर वादों के क्षेत्र के बाहर सार्वजनिक कानून के आधार पर खाते के लिए। वर्तमान में, वचनपत्र क्षेत्र के

बाहर वचनबद्धता के समान सिद्धांत के अभाव में, नीतियों के पुनर्वितरण का प्रशासनिक कानून अधिनिर्णय एक अस्थिर सार्वजनिक कानून नींव पर खड़ा है।“

38. इसलिए हम वैध अपेक्षा के सिद्धांत के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने का प्रयास करेंगे, जो केवल वचन पत्र के सिद्धांत के साथ सादृश्य पर आधारित नहीं है। इस सिद्धांत के स्वतंत्र अस्तित्व की आवश्यकता को संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फ्रैंकफर्टर द्वारा **विटारेली बनाम सेटन**[28] में व्यक्त किया गया था:

"एक कार्यकारी एजेंसी को सख्ती से उन मानकों पर रखा जाना चाहिए जिनके द्वारा वह न्याय करने के लिए अपनी कार्रवाई का दावा करती है। तदनुसार, यदि रोजगार से बर्खास्तगी एक परिभाषित प्रक्रिया पर आधारित है, भले ही ऐसी एजेंसी को बाध्य करने वाली आवश्यकताओं से परे उदार हो, तो उस प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। न्यायिक रूप से विकसित प्रशासनिक कानून का यह नियम अब दृढ़ता से स्थापित हो चुका है और यदि मैं इसमें कुछ भी जोड़ दूं तो यह ठीक ही है। जो प्रक्रियात्मक तलवार उठाएगा वह तलवार से नष्ट हो जाएगा।

39. हालांकि, ऐसा करने से पहले, इस न्यायालय के पिछले निर्णयों में वैध अपेक्षा के सिद्धांत की समझ को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। **नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन बनाम एस. रघुनाथन**[29] **("नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन**") में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद के माध्यम से बोलते हुए कहा कि:

"18. "वैध अपेक्षा" के सिद्धांत की उत्पत्ति प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में हुई है। देश के मामलों का प्रशासन करने में सरकार और उसके विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नीति या इरादे के बयानों का सम्मान करें और नागरिकों के साथ विवेक के दुरुपयोग के बिना पूर्ण व्यक्तिगत विचार के साथ व्यवहार करें। नीतिगत विवरणों की अनुचित रूप से अवहेलना नहीं की जा सकती है या चुनिंदा रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अतार्किकता के रूप में अनुचितता प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के समान है। यह इस संदर्भ में

---

[28] 359 यूएस 535 (1959); इस निर्णय में दिए गए सिद्धांत का इस न्यायालय द्वारा अमरजीत सिंह अहलूवालिया (डॉ) बनाम पंजाब राज्य, (1975) 3 एससीसी 503, सुखदेव सिंह बनाम भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी, (1975) 1 एससीसी 421 (न्यायमूर्ति केके मैथ्यू की सहमति के साथ) और रमण दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, (1979) 3 एससीसी 489 में इस निर्णय में अनुसरण किया गया है।

[29] (1998) 7 एससीसी 66

था कि "वैध अपेक्षा" का सिद्धांत विकसित किया गया था जो आज वास्तविक और साथ ही प्रक्रियात्मक अधिकारों का स्रोत बन गया है। लेकिन "<u>वैध उम्मीद" पर आधारित दावों को अभ्यावेदन पर निर्भरता की आवश्यकता होती है और इसके परिणामस्वरूप दावेदार को उसी तरह से नुकसान होता है जैसे कि वचनबद्धता के आधार पर दावे।</u>

(महत्त्व सन्निविष्ट)

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अवलोकन इस न्यायालय द्वारा अंग्रेजी कानून के तहत वैध अपेक्षा के सिद्धांत के दायरे पर चर्चा करते हुए किया गया था, जैसा कि तब खड़ा था। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, अंग्रेजी कानून के तहत भी वैध अपेक्षा और वचनबद्धता के सिद्धांतों के बीच पर्याप्त टकराव या ओवरलैप था क्योंकि पूर्व को अक्सर बाद के अनुरूप होने के रूप में लागू किया जाता था। हालाँकि, तब से और **राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम** (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के बाद से, वैध अपेक्षा के सिद्धांत के संबंध में अंग्रेजी कानून विकसित हुआ है। अधिक विशेष रूप से, इसने सक्रिय रूप से दो सिद्धांतों को अलग करने और व्यापक स्तर पर वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश की है। **रेजिना (रेप्रोटेक (पेबशम) लिमिटेड) बनाम ईस्ट ससेक्स काउंटी काउंसिल**[30] में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस प्रकार आयोजित किया है

(महत्व दिया गया)

"33 किसी भी मामले में, मुझे लगता है कि नियोजन कानून में एस्टोपेल की निजी कानून अवधारणाओं को पेश करना अनुपयोगी है। जैसा कि लॉर्ड स्कारमैन ने न्यूबरी जिला परिषद बनाम पर्यावरण राज्य सचिव [1981] ए सी 578, 616 में बताया, <u>विबन्धन व्यक्तियों को इस आधार पर बांधते हैं कि उनके लिए यह अविवेकपूर्ण होगा कि उन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया है या सहमत हुए हैं, उससे इनकार करें। लेकिन निजी कानून की इन अवधारणाओं</u>

[30] [2003] 1 डब्ल्यूएलआर 348

को "नियोजन नियंत्रण के सार्वजनिक कानून, जो सभी को बांधता है" में विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए। (आर वी लीसेस्टर सिटी काउंसिल में डायसन जे भी देखें, एक्स पी पॉवरजेन यूके लिमिटेड [2000] जेपीएल 629 , 637।

34. निश्चित रूप से एक निजी कानून एस्टोपेल और एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा बनाई गई वैध अपेक्षा की सार्वजनिक कानून अवधारणा के बीच एक सादृश्य है, जिसका इनकार शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है ... लेकिन यह एक सादृश्य से अधिक नहीं है क्योंकि सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ उपायों को आम जनता के हितों को भी ध्यान में रखना पड़ता है जिसे बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण मौजूद है। सार्वजनिक कानून मानवाधिकार अधिनियम 1998 के तहत मौजूद व्यक्तिगत अधिकारों के पदानुक्रम को भी ध्यान में रख सकता है, ताकि, उदाहरण के लिए, घर में व्यक्ति के अधिकार को उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाए (देखें कफलान का मामला, पीपी 254-255 पर) जबकि सामान्य संपत्ति के अधिकार सामान्य रूप से सार्वजनिक हित के विचारों से कहीं अधिक सीमित हैं: आर (अल्कोनबरी डेवलपमेंट्स लिमिटेड) बनाम पर्यावरण, परिवहन और क्षेत्रों के लिए राज्य सचिव [2001] 2 डब्ल्यूएलआर 1389 देखें।

35. यह सच है कि वेल्स केस [1967] 1 WLR 1000 और लीवर फाइनेंस लिमिटेड बनाम वेस्टमिंस्टर (सिटी) लंदन बरो काउंसिल [1971] 1 QB 222 जैसे शुरुआती मामलों में, लॉर्ड डेनिंग एमआर ने नियोजन कानून के संबंध में एस्टोपेल की भाषा का इस्तेमाल किया। उस समय सत्ता के दुरुपयोग और वैध अपेक्षा की सार्वजनिक कानून अवधारणाएं बहुत अविकसित थीं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि एस्टोपेल की समानता उपयोगी लग रही थी..... मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में, सार्वजनिक कानून ने पहले से ही नैतिक मूल्यों से जो कुछ भी उपयोगी है, उसे अवशोषित कर लिया है जो एस्टोपेल की निजी कानून अवधारणा को रेखांकित करता है और इसके लिए अपने दो पैरों पर खड़े होने का समय आ गया है।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

40. **मोनेट इस्पात एवं ऊर्जा लिमिटेड बनाम भारत संघ**[31] (**"मोनेट इस्पात")** में एक सहमति की राय में, न्यायमूर्ति एच एल गोखले ने विभिन्न विचारों पर प्रकाश डाला जो वचन और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि वचनबद्धता के सिद्धांत के आवेदन के लिए, एक वादा होना चाहिए, जिसके आधार पर वादा करने वाले ने अपने पूर्वाग्रह का काम किया है। इसके विपरीत, वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करते समय, प्राथमिक विचार राज्य की कार्रवाई की तर्कसंगतता और निष्पक्षता हैं। उन्होंने इस प्रकार देखा:

"वचन पत्र और वैध उम्मीदें

289. <u>जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, वचनबद्धता के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक वादा होना चाहिए, और उस आधार पर संबंधित पक्ष ने अपने पूर्वाग्रह से काम किया होगा।</u> वर्तमान मामले में यह केवल एक प्रस्ताव था और यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि इसे केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना था, इससे पहले इसे वायदे वाला नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा, का उपयोग वैधानिक प्रावधान या अधिसूचना के खिलाफ नहीं किया जा सकता है।

290..... किसी भी मामले में, किसी भी वादे के अभाव में, आधुनिक सहित अपीलकर्ता प्रासंगिक वैधानिक शक्तियों के तहत जारी अधिसूचनाओं के दांतों में वचनपत्र का दावा नहीं कर सकते हैं। <u>वैकल्पिक रूप से, अपीलकर्ता वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत के तहत मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं।</u> इस सिद्धांत का आधार तर्कसंगतता और निष्पक्षता में है। हालांकि, इसे भी लागू नहीं किया जा सकता है जहां सार्वजनिक प्राधिकरण का निर्णय कानून के प्रावधान में स्थापित किया गया है, और सार्वजनिक हित के अनुरूप है।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

41. **भारत संघ बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी**[32] में, मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर के माध्यम से बोलते हुए, न्यायालय ने **मोनेट इस्पात** (सुप्रा) में निर्णय पर चर्चा की

---

[31] (2012) 11 एससीसी 1

[32] (2016) 4 एससीसी 236

और **न्यू साउथ वेल्स** बनाम **क्विन**[33] के अटॉर्नी जनरल के फैसले पर अपनी निर्भरता को नोट किया। इसके बाद यह देखा गया:

"इस न्यायालय ने कहा कि यदि किसी दिए गए मामले में वैध अपेक्षा से इनकार करना किसी ऐसे अधिकार से वंचित करने के बराबर है जो गारंटीकृत है या मनमाना, भेदभावपूर्ण, अनुचित या पक्षपातपूर्ण, शक्ति का घोर दुरुपयोग या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 को लागू करने वाले प्रसिद्ध आधारों पर इस पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन बिना किसी और चीज के केवल वैध अपेक्षा के आधार पर दावा नहीं किया जा सकता है वास्तव में इन सिद्धांतों को लागू करने का अधिकार दें। इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि वैध अपेक्षा के सिद्धांत को अपने आप में एक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब वैध अपेक्षा से इनकार करने से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।"

42. अनुच्छेद 14 और वैध अपेक्षा के सिद्धांत के बीच संबंध के संबंध के संबंध में, **भारतीय खाद्य निगम** बनाम **कामधेनु मवेशी चारा उद्योग**[34] में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति जे एस वर्मा के माध्यम से बोलते हुए इस प्रकार कहा:

"7. संविदात्मक क्षेत्र में अन्य सभी राज्य कार्यों की तरह, राज्य और उसके सभी तंत्रों को संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होना चाहिए, जिसका गैर-मनमानापन एक महत्वपूर्ण पहलू है। सार्वजनिक कानून में कोई निरंकुश विवेक नहीं है: एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास केवल सार्वजनिक भलाई के लिए उनका उपयोग करने की शक्तियाँ हैं। यह निष्पक्ष रूप से कार्य करने और एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने का कर्तव्य लगाता है जो 'कार्रवाई में निष्पक्षता' है। अच्छे प्रशासन के एक हिस्से के रूप में इस दायित्व का उचित पालन प्रत्येक नागरिक में राज्य और उसके तंत्रों के साथ बातचीत में उचित या वैध व्यवहार करने की अपेक्षा करता है, इस तत्व के साथ सभी राज्य कार्यों में निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक बनता है। <u>राज्य की कार्रवाई में गैर-मनमानेपन की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, इसलिए, 32 (2016) 4 एससीसी 236 से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की उचित</u>

---

[33] (1990) 64 ऑस्ट एलजेआर 327: (1990) 170 सीएलआर 1.

[34] (1993) 1 एससीसी 71

या वैध अपेक्षाओं पर विचार करना और उचित वजन देना आवश्यक है। या फिर यह कि शक्ति के प्रयोग में अनुचितता किसी दिए गए मामले में निर्णय की सदाशयता को प्रभावित करने के अलावा शक्ति का दुरुपयोग या अधिकता हो सकती है। इस प्रकार लिए गए निर्णय को मनमानेपन के आधार पर चुनौती दी जाएगी। कानून का शासन शक्ति के प्रयोग में विवेक को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है, क्योंकि यह अवास्तविक है, लेकिन न्यायिक समीक्षा द्वारा इसके प्रयोग के नियंत्रण का प्रावधान करता है।

8. ऐसी स्थिति में किसी नागरिक की केवल उचित या वैध अपेक्षा, अपने आप में एक विशिष्ट प्रवर्तनीय अधिकार नहीं हो सकती है, लेकिन इस पर विचार करने और उसे उचित वजन देने में विफलता निर्णय को मनमाना बना सकती है, और इस तरह एक वैध अपेक्षा पर उचित विचार की आवश्यकता गैर-मनमानेपन के सिद्धांत का हिस्सा बनती है, कानून के शासन का एक आवश्यक सहगामी। प्रत्येक वैध अपेक्षा एक प्रासंगिक कारक है जिसे निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित विचार की आवश्यकता होती है। दावेदार की अपेक्षा संदर्भ में उचित या वैध है या नहीं, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है। जब भी सवाल उठता है, यह दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं बल्कि बड़े सार्वजनिक हित में निर्धारित किया जाना है, जिसमें अन्य अधिक महत्वपूर्ण विचार दावेदार की वैध अपेक्षा से अधिक हो सकते हैं. इस तरीके से सार्वजनिक प्राधिकरण का एक सदाशयी निर्णय गैर-मनमानेपन की आवश्यकता को पूरा करेगा और न्यायिक जांच का सामना करेगा। वैध अपेक्षा का सिद्धांत कानून के शासन में आत्मसात हो जाता है और हमारी कानूनी प्रणाली में इस तरीके से और इस हद तक संचालित होता है।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

हाल ही में, **नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन** बनाम **नोएडा**[35] में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति बीएस चौहान के माध्यम से बोलते हुए, निम्नलिखित शब्दों में इस संबंध पर विस्तार से बताया:

---

[35] (2011) 6 एससीसी 508

"39. राज्य की कार्रवाइयों को संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर गैर-मनमाना और उचित ठहराया जाना आवश्यक है। राज्य की कार्रवाई या उसके साधन कुछ सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए जो तर्क और प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। "सरकार के लोकतांत्रिक रूप का कामकाज समानता और मनमानेपन और भेदभाव की अनुपस्थिति की मांग करता है"। कानून का शासन 35 (2011) 6 एससीसी 508 को प्रतिबंधित करता है। मनमानी कार्रवाई और संबंधित प्राधिकरण को कानून के अनुसार कार्य करने का आदेश देता है। राज्य या उसके तंत्र की हर कार्रवाई न तो भेदभाव का संकेत देने वाली होनी चाहिए, न ही स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह, पक्षपात और भाई-भतीजावाद का आभास देना चाहिए। यदि कोई निर्णय बिना किसी सिद्धांत या किसी नियम के लिया जाता है, तो यह अप्रत्याशित होता है और ऐसा निर्णय कानून के शासन के अनुसार लिए गए निर्णय के विपरीत होता है

..

41. किसी लोक प्राधिकरण में राज्य द्वारा निहित शक्ति को वृहत्तर सार्वजनिक और सामाजिक हित में प्रयोग किए जाने वाले कर्तव्य के साथ एक न्यास के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी मामले के वैधानिक प्रावधानों और तथ्य स्थिति का सख्ती से पालन करते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाना <u>है। "सार्वजनिक प्राधिकरण उनमें निहित शक्तियों के साथ तेजी से और ढीले नहीं खेल सकते हैं। मनमाने तरीके से लिया गया निर्णय वैध अपेक्षा के सिद्धांत के विपरीत है। एक प्राधिकरण एक कानूनी दायित्व के तहत है कि वह शक्ति का प्रयोग यथोचित और सद्भाव में उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए करे जिसके लिए शक्ति प्रदान की गई थी। इस संदर्भ में, "अच्छे विश्वास में" का अर्थ है "वैध कारणों से"। इसका प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और किसी अन्य के लिए नहीं..."</u>

(महत्त्व सन्निविष्ट)

इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि वास्तविक वैध अपेक्षा का सिद्धांत उन तरीकों में से एक है जिसमें अनुच्छेद 14 के तहत निहित गैर-मनमानेपन की गारंटी ठोस अभिव्यक्ति पाती है।

H.6. झारखंड राज्य द्वारा तोड़ी गई अपेक्षाएं

43. वर्तमान मामले में उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम राज्य के प्रस्तुत करने में किसी भी पदार्थ को देखने में असमर्थ हैं, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष बचाव में आग्रह किया गया था। वर्तमान मामले में न केवल राज्य ने एक गंभीर प्रतिनिधित्व किया, बल्कि यह प्रतिनिधित्व राज्य में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने की अपनी घोषित इच्छा पर स्थापित किया गया था। नीति दस्तावेज में कहा गया है:

(i) प्रोत्साहनों की प्रकृति;

(ii) वह अवधि जिसके दौरान प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे; और

(iii) वह समय सीमा जिसके भीतर औद्योगिक नीति 2012 को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने विभागों के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी

44. राज्य ने उपरोक्त शर्तों में एक गंभीर प्रतिनिधित्व किया है, यह स्पष्ट रूप से अनुचित और मनमाना होगा कि राज्य के भीतर औद्योगिक इकाइयों को उनके वैध अधिकार से वंचित किया जाए। राज्य सरकार ने वास्तव में, धारा 9 के तहत एक वैधानिक अधिसूचना जारी की, लेकिन 8 जनवरी 2015 से प्रभावी रूप से ऐसा करके इसने औद्योगिक नीति 2012 में प्रतिनिधित्व की प्रकृति को नकार दिया। अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष नीति या जनहित के कारणों पर असर डालने वाला कोई औचित्य पेश नहीं किया गया है। दलीलें सरकार की ओर से देरी के कारणों पर पूरी तरह से चुप हैं और औद्योगिक नीति 2012 में प्रतिनिधित्व की शर्तों के विपरीत, छूट को भावी बनाने के लिए कोई औचित्य प्रदान नहीं करती हैं।

45. राज्य के लिए यह दावा करना एक बात है कि रिट याचिकाकर्ता के पास कोई निहित अधिकार नहीं था, लेकिन राज्य के लिए यह दावा करना एक और बात है कि औद्योगिक नीति 2012 में परिकल्पित अवधि के भीतर छूट अधिसूचना को प्रभावी नहीं करने के अपने कारणों का खुलासा करना कर्तव्य नहीं है। राज्य की जवाबदेही और नीतिगत दस्तावेज के संदर्भ में उसने जो गंभीर दायित्व निभाया है, दोनों ही राज्य शक्ति की ऐसी धारणा को स्वीकार करने के खिलाफ हैं। राज्य को औपनिवेशिक धारणा को त्याग देना चाहिए कि यह एक संप्रभु है जो अपनी इच्छा से खैरात सौंपता है। इसकी नीतियां वैध

अपेक्षाओं को जन्म देती हैं कि राज्य सार्वजनिक दायरे में जो कुछ भी सामने रखता है उसके अनुसार कार्य करेगा। अपने सभी कार्यों में, राज्य निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य है। यह मनमानी राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी की एक प्राथमिक आवश्यकता है जिसे संविधान का अनुच्छेद 14 अपनाता है। निजी नागरिकों और निजी व्यवसाय के अधिकार से वंचित होना सार्वजनिक हित में आधारित आवश्यकता के अनुपात में होना चाहिए। राज्य शक्ति की इस अवधारणा को इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक सुसंगत पंक्ति में मान्यता दी गई है। एक उदाहरण के रूप में, हम **राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम** (सुप्रा) में इस न्यायालय की टिप्पणियों को निकालना चाहते हैं:

> "देश के मामलों का प्रशासन करने वाले सरकार और उसके विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नीति या इरादे के बयानों का सम्मान करें और नागरिकों के साथ विवेकाधिकार के दुरुपयोग के बिना पूर्ण व्यक्तिगत विचार के साथ व्यवहार करें। नीतिगत विवरणों की अनुचित रूप से अवहेलना नहीं की जा सकती है या चुनिंदा रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अतार्किकता के रूप में अनुचितता प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के समान है।"

46. इसलिए, यह स्पष्ट है कि राज्य ने औद्योगिक नीति 2012 के तहत प्रतिवादी और इसी तरह स्थित औद्योगिक इकाइयों को एक प्रतिनिधित्व दिया था। इस अभ्यावेदन ने उनकी ओर से एक जायज अपेक्षा को जन्म दिया कि उन्हें अगले पांच वर्षों के लिए बिजली शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट/कटौती की पेशकश की जाएगी। हालांकि, निर्धारित समय के भीतर अधिसूचना जारी करने में विफलता के कारण और केवल भावी रूप से छूट प्रदान करने के कारण, राज्य में अपेक्षा और विश्वास का उल्लंघन हुआ। चूंकि राज्य ने अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए कोई औचित्य नहीं दिया है, या इसके सार्वजनिक हित में होने के कारण बताए हैं, हम मानते हैं कि राज्य द्वारा इस तरह की कार्रवाई मनमानी है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

H.7. दावे के लिए तकनीकी बचाव

(i) अनुच्छेद 226 47 का आकलन और सहारा.

हम प्रतिवादी की तकनीकी बारीकियों पर राज्य के प्रस्तुतिकरण से प्रभावित नहीं हुए हैं, जिसने अपने मूल्यांकन रिटर्न में बिजली शुल्क से छूट का दावा दायर नहीं किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि धारा 9 के तहत कोई छूट अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, इसलिए उषा मार्टिन लिमिटेड द्वारा शुरू में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। रिट याचिका के परिणामस्वरूप, 8 जनवरी 2015 को एक छूट अधिसूचना जारी की गई थी। अब यह सही है कि वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के मामले में, मूल्यांकन के आदेश 8 दिसंबर 2015 और 16 दिसंबर 2016 को पारित किए गए थे, जो छूट अधिसूचना की तारीख के बाद थे। हालांकि, तथ्य यह है कि जब तक छूट अधिसूचना में खंड इसे संभावित प्रभाव प्रदान करता है, तब तक क्षेत्र को बनाए रखना जारी रखता है, क़ानून के प्राणी के रूप में मूल्यांकन अधिकारी छूट की शर्तों को लागू करने के लिए बाध्य था और तदनुसार 8 जनवरी 2015 से पहले की अवधि के लिए किसी भी छूट से इनकार कर दिया। एकमात्र उपाय जो प्रतिवादी के लिए उपलब्ध था, वह छूट अधिसूचना की शर्तों को चुनौती देना था जो उसने अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही शुरू करके किया था।

(ii) देरी का तर्क

48. अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत करने का गंभीर प्रयास किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि वे 2019 में स्थापित किए गए थे.हालांकि, उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वकील श्री देवाशीष भारुका ने अपनी प्रस्तुतियों के दौरान, सही ढंग से आग्रह किया है कि देरी का मुद्दा कभी भी ए बी सी डी ई के समक्ष कार्यवाही के दौरान नहीं उठाया गया है एफ जी एच 81 उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका में एक आधार के रूप में उठाया गया। **पटना उच्च न्यायालय बनाम मदन मोहन प्रसाद,**[36] में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति जे एम पांचाल के माध्यम से बोलते हुए इस प्रकार कहा:

"19. अपीलकर्ता की ओर से दिया गया तर्क कि रिट याचिका प्रतिवादी 1 द्वारा 10-11-1990 को दायर की गई थी, यानी सेवा से सेवानिवृत्त होने के सात साल बाद,

---

[36] (2011) 9 एससीसी 65

और इसलिए, रिट याचिका को देरी और लापरवाही के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आक्षेपित निर्णय कहीं भी यह नहीं दर्शाता है कि अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष इस तरह के बिंदु पर बहस की गई थी। एसएलपी के ज्ञापन में कोई शिकायत नहीं की गई है कि देरी और लापरवाही के बारे में उच्च न्यायालय के समक्ष बहस की गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया था जब निर्णय दिया गया था। इसके अलावा, श्री भारुका ने प्रस्तुत किया है कि एक बार जब उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की रिट याचिका को योग्यता के आधार पर कानूनी रूप से टिकाऊ माना है, तो इस न्यायालय को केवल देरी और लापरवाही के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसे **दयाल सिंह** बनाम **भारत संघ**[37] में इस न्यायालय के फैसले में समर्थन मिलता है, जहां तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा के माध्यम से बोलते हुए इस प्रकार कहा:

> "41. यह प्रस्तुत किया गया था कि उत्तरदाताओं ने आठ साल की अवधि के बाद एक रिट याचिका दायर की है, उसी पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। मुख्य रूप से विलंब और कमी का प्रश्न एक ऐसा मामला है जिस पर रिट न्यायालय द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है। एक बार जब रिट कोर्ट ने उत्तरदाताओं की ओर से देरी और लापरवाही के बावजूद अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, तो इस स्तर पर यह हमारे लिए नहीं है कि हम अकेले उस आधार पर उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करें, खासकर जब हम पाते हैं कि आक्षेपित निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ है।

श्री भारुका यह प्रस्तुत करने में भी सही हैं कि राज्य संभवतः यह तर्क नहीं दे सकता है कि देरी के परिणामस्वरूप उसने अपनी स्थिति को अपने नुकसान के लिए बदल दिया है। न ही यह ऐसा मामला है जहां रिट कार्यवाही शुरू करने में देरी के परिणामस्वरूप तीसरे पक्ष प्रभावित हो सकते हैं। इस सबमिशन को **हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड** बनाम **डॉली दास**[38] में समर्थन मिलता है, जहां दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू के माध्यम से बोलते हुए इस प्रकार नोट किया: 36 (2011) 9 एससीसी 65। 37 (2003) 2 एससीसी 593। 38(1999) 4 एससीसी 450

---

[37] (2003) 2 एससीसी 593

[38] (1999) 4 एससीसी 450

"8. जहां तक रिट याचिका दायर करने में प्रतिवादी के संबंध में विवाद का संबंध है, देरी, अपने आप में, राहत के लिए दावे को तब तक पराजित नहीं कर सकती जब तक कि अपीलकर्ता की स्थिति को इस तरह से बदल नहीं दिया गया हो, जिसे समय की कमी या दूसरे पक्ष की निष्क्रियता के कारण वापस नहीं लिया जा सकता है। यह पहलू मामले के तथ्यों की जांच पर निर्भर करता है और इस तरह की दलील उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई है, इसलिए अपीलकर्ताओं को हमारे समक्ष पहली बार इस तरह की दलील उठाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। इसके अलावा, हम देख सकते हैं कि जिस अवधि के लिए नवीकरण का विकल्प चुना गया है, वह समाप्त नहीं हुआ है। ऐसी अवधि के निर्वाह के दौरान निश्चित रूप से प्रतिवादी यह शिकायत कर सकता है कि विकल्प का ऐसा प्रयोग अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं था और इसलिए, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाद के चरण में भी लागू किया जा सकता है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं को राहत के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क करने में इस देरी के कारण किसी भी तरह से अनुचित कठिनाई में नहीं डाला जाता है।

मामले के इस दृष्टिकोण में, हम केवल देरी के आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं जब निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ सिद्धांतों पर आधारित है। रिट याचिका दायर करने में प्रतिवादी की देरी को अपने आप में दावे को पराजित नहीं करना चाहिए जब तक कि राज्य की स्थिति को इतना बदल नहीं दिया गया हो कि इसे समय की कमी या रिट याचिकाकर्ता की निष्क्रियता के कारण वापस नहीं लिया जा सकता है। राज्य ने वर्तमान मामले में प्रतिवादी को राहत दिए जाने पर किसी भी कठिनाई की वकालत या तर्क नहीं दिया है। अंत में, **भाईलाल भाई** (सुप्रा) और **सुगनमल** (सुप्रा) में निर्णय एक याचिकाकर्ता से संबंधित थे जो अवैध रूप से एकत्र किए गए कर की वापसी की मांग कर रहे थे। वर्तमान मामले में, हम ऐसी स्थिति से चिंतित नहीं हैं। बल्कि, याचिकाकर्ता राज्य की कार्रवाई में मनमानी के कारण इस न्यायालय के समक्ष आया है जिसके कारण उनकी वैध अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई।

(iii) अन्यायपूर्ण संवर्धन की रक्षा

49. न ही अदालत अन्यायपूर्ण संवर्धन की दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है - उच्च न्यायालय ने शुल्क का भुगतान किए जाने के बाद से धनवापसी का आदेश नहीं दिया है। प्रतिवादी को भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क के समायोजन से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य का यह कहना कि उच्च न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा इस बात पर कोई दलील नहीं दी गई थी कि क्या प्रतिवादी द्वारा छूट/कटौती के रूप में दावा की जा रही राशि को प्रतिवादी द्वारा अपने ग्राहकों को दिया गया था, तथ्यात्मक रूप से गलत है। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में, प्रतिवादी ने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि राज्य द्वारा प्रतिवादी से वसूले गए बिजली शुल्क की अंतर राशि का बोझ उत्तरार्द्ध द्वारा अपने ग्राहकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य तरीके से पारित नहीं किया गया था। प्रतिवादी की रिट याचिका में दलील का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

> "41. कि, इस स्तर पर, यह सबसे विनम्रतापूर्वक कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता को बिजली शुल्क की 50% राशि वापस कर दी जाती है, तो इससे याचिकाकर्ता के हाथों में अन्यायपूर्ण संवर्धन नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता से प्रतिवादी-राज्य द्वारा महसूस की गई बिजली शुल्क की अंतर राशि का बोझ नहीं डाला है। अपने ग्राहकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य तरीके से।"
>
> 42. यह सबसे विनम्रतापूर्वक कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत अवधि के लिए प्रतिवादी-राज्य झारखंड द्वारा याचिकाकर्ता से 100% बिजली शुल्क वसूल किया गया है और इस प्रकार, अतिरिक्त 50% बिजली शुल्क याचिकाकर्ता द्वारा वहन किया गया है अपनी जेब से और उसी का बोझ याचिकाकर्ता द्वारा अपने ग्राहकों को नहीं दिया जा सकता है।
>
> 43. यह सबसे विनम्रतापूर्वक कहा और प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता स्पंज आयरन और एम एस बिलेट का निर्माता है और उक्त वस्तु की कीमत बाजार संचालित है और बाजार द्वारा नियंत्रित है। याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई बिजली शुल्क की राशि अपनी जेब से बाहर थी, जिससे याचिकाकर्ता के अंतिम उत्पाद की बिक्री पर सकल लाभ प्रभावित हुआ। यह स्पष्ट रूप से

दोहराया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने ग्राहकों पर बिजली की मात्रा का बोझ नहीं डाला गया है।

जहां तक **मफतलाल इंडस्ट्रीज** (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर याचिकाकर्ता की निर्भरता का संबंध है, हम न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी के बहुमत की राय में निम्नलिखित शब्दों में खुद और चार अन्य विद्वान न्यायाधीशों के लिए बोलते हुए विज्ञापन देना चाहते हैं:

> "108 (iii)। धनवापसी के लिए दावा, चाहे वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया हो जैसा कि ऊपर प्रस्ताव (i) में विचार किया गया है या ऊपर प्रस्ताव (ii) द्वारा विचारित स्थितियों में एक वाद या रिट याचिका में किया गया है, केवल तभी सफल हो सकता है जब याचिकाकर्ता/वादी आरोप लगाता है और स्थापित करता है कि उसने किसी अन्य व्यक्ति/अन्य व्यक्तियों पर कर्तव्य का बोझ नहीं डाला है। उसके धनवापसी दावे की अनुमति/डिक्री केवल तभी दी जाएगी जब वह यह स्थापित कर लेता है कि उसने कर्तव्य का बोझ नहीं डाला है या उस सीमा तक नहीं दिया है जिस हद तक उसने ऐसा नहीं किया है, जैसा भी मामला हो। चाहे बहाली के दावे को संवैधानिक अनिवार्यता के रूप में या वैधानिक आवश्यकता के रूप में माना जाता है, यह न तो एक पूर्ण अधिकार है और न ही बिना शर्त दायित्व है, लेकिन उपरोक्त आवश्यकता के अधीन है, जैसा कि निर्णय के शरीर में बताया गया है। जहां कर्तव्य का बोझ पारित किया गया है, दावेदार यह नहीं कह सकता कि उसे कोई वास्तविक नुकसान या पूर्वाग्रह हुआ है। ऐसे मामले में वास्तविक नुकसान या पूर्वाग्रह उस व्यक्ति द्वारा भुगता जाता है जिसने अंततः बोझ उठाया है और यह केवल वह व्यक्ति है जो वैध रूप से इसके धनवापसी का दावा कर सकता है। लेकिन जहां ऐसा व्यक्ति आगे नहीं आता है या जहां किसी न किसी कारण से उसे राशि वापस करना संभव नहीं है, तो यह उचित है कि उस राशि को राज्य द्वारा अर्थात् लोगों द्वारा रखा जाए। इस तरह के प्रस्ताव में कोई अनैतिकता या अनौचित्य शामिल नहीं है।

अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत एक न्यायसंगत और हितकारी सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति दोनों ओर से शुल्क वसूलने की मांग नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वह एक छोर पर अपने क्रेता से शुल्क एकत्र नहीं कर सकता है और राज्य से भी उसी शुल्क को इस आधार पर एकत्र नहीं कर सकता है कि यह कानून के विपरीत उससे एकत्र किया गया है। न्यायालय की शक्ति का उपयोग किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध करने के लिए नहीं किया जाना है।

वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने पहले आयोजित किया है, वर्तमान प्रतिवादी ने उपरोक्त वाक्यांशों को तैनात करने के लिए दोनों सिरों से बिजली शुल्क एकत्र नहीं किया। नतीजतन, इस सिद्धांत का मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

50. **भरतीय पर्यावरण कानूनी कारेवाई परिषद बनाम भारत संघ**[39] में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी के माध्यम से बोलते हुए, निम्नलिखित शब्दों में अन्यायपूर्ण संवर्धन के अवयवों को रेखांकित किया:

"152. "अन्यायपूर्ण संवर्धन" को न्यायालय द्वारा दूसरे के नुकसान के लाभ के अन्यायपूर्ण प्रतिधारण के रूप में परिभाषित किया गया है, या न्याय या इक्विटी और अच्छे विवेक के मूल सिद्धांतों के खिलाफ दूसरे के धन या संपत्ति की अवधारण। एक व्यक्ति को समृद्ध किया जाता है यदि उसे लाभ प्राप्त हुआ है, और यदि लाभ का प्रतिधारण अन्यायपूर्ण होगा तो वह अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध होता है। किसी व्यक्ति का अन्यायपूर्ण संवर्धन तब होता है जब उसके पास धन या लाभ होता है जो न्याय और इक्विटी में दूसरे के होते हैं। इस परिभाषा को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत आकर्षित किया जा सकता था यदि प्रतिवादी ने अपने ग्राहकों को बिजली शुल्क दिया होता और फिर 50 प्रतिशत छूट के कारण रिफंड को अपनी जेब में रख लिया होता। यह तथ्यात्मक स्थिति के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है और इसलिए, प्रतिवादी को सिद्धांत के आवेदन पर राहत से वंचित नहीं किया जा सकता है

---

[39] (2011) 8 एससीसी 161

I. निष्कर्ष

51. संकीर्ण मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी बिजली शुल्क से छूट/कटौती का हकदार है जिसका उत्तर सकारात्मक में दिया गया है। तथापि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रतिवादी वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए छूट/कटौती का हकदार नहीं होगा। औद्योगिक नीति 2012 के खंड 35.7 (बी) के अनुसार, पात्रता उत्पादन शुरू होने के बाद वित्तीय वर्ष से शुरू होती है। प्रतिवादी ने 17 अगस्त 2011 को उत्पादन शुरू किया। इसलिए, वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करनी होगी। अंत में, हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत हैं कि प्रतिवादी बिजली शुल्क से छूट का हकदार था, हालांकि इस फैसले में बताए गए कारणों के लिए। इसके अलावा, दी गई राहत वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 तक ही सीमित रहेगी। अपीलों का निपटान उपर्युक्त शर्तों में किया जाएगा। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

52. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान कर दिया गया है।

अंकित ज्ञान अपील का निस्तारण

<u>यह अनुवाद तलत परवीन, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>